19 अगस्त, 2026 बुधवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 139

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com | Email : timesofpedia@gmail.com

आईपीएल में खिलाड़ियों को ट्रेड किये जाने की रकम का खुलासा करें फ्रेंचाइजी : गावस्कर 07

संक्षिप्त वार्ता

ईरान से युद्ध कर फंसे ट्रंप! अमेरिकी एयरक्राफ्ट का बुरा हाल

वॉशिंगटन। ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिका फंसा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस लंबी खिंचती लड़ाई से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत खराब है। अमेरिका इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 260 दिनों से अरब सागर में फंसा है। एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें उसके टॉयलेट जाम दिख रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि इस पर तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन के एक ताजा टिकटॉक वीडियो में टॉयलेट बहता हुआ दिख रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के खराब खाने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। एक अन्य वीडियो में बाथरूम का फ्लोर गंदा नजर आ रहा है और पाइप में जंग लगी है। टॉयलेट में भूरे रंग का लिक्विड दिखाई दे रहा है। अमेरिकी नौसेना ने अभी इन वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस वीडियो में मौजूद एक अमेरिकी नौसैनिक हालात को भयानक बताता दिख रहा है। उसने टॉयलेट की खराब स्थिति को वीडियो में दिखाया है।

जाम्बिया के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हाकाइंडे हिचिलेमा

लुसाका। जाम्बिया के निर्वाचन आयोग ने मंगलवार सुबह घोषणा की कि राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुने गए हैं। हिचिलेमा को गत गुरुवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। इसके लिए किसी ह्वारन-ऑफह्न की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मतदान के दौरान डाले गए 50 लाख वोट में से 61.4 फीसदी वोट हिचिलेमा के पक्ष में पड़े।

इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी थीं। चुनाव में पिछले शुक्रवार को मतों की गिनती रोक दी गई थी और कुछ घंटों बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इसे फिर से शुरू किया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बताया था कि कुछ मतदान केंद्र के अधिकारियों पर हमले हुए थे और मत पत्र चोरी हो गए थे। सरकार ने यह भी पुष्टि की कि चुनाव की रात विपक्ष के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया था।

ट्रंप-शी की होगी मुलाकात, लेकिन यूएनजीए से दूर रहेंगे चीनी राष्ट्रपति

वॉशिंगटन। दुनिया की दो महाशक्तियां और एक दूसरे की धुर प्रतिद्वंद्वी होने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आगामी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होने वाली बहुप्रतीक्षित मुलाकात वैश्विक सुर्खियों में है। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, इस उच्च-स्तरीय मुलाकात को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक चीन के राष्ट्रपति इस अमेरिकी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में हिस्सा नहीं लेंगे। जानकारी के अनुसार, शी जिनपिंग 23 सितंबर की देर शाम अमेरिका पहुंच सकते हैं और अगले दिन यानी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 सितंबर को उनके अमेरिका से रवाना होने की संभावना है।

मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एक्स पर दिया एकजुटता पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया, जिसमें आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने संस्कृत का श्लोक, उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम्। अप्यपर्वणि भज्येत न नमत्वेव कस्यचित्॥ साझा किया।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि मनुष्य को सदैव अपने आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे, बल्कि सत्य, धैर्य और आत्मगौरव के साथ अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। यह संदेश राष्ट्र निर्माण में नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत दृढ़ता की भूमिका को रेखांकित करता है।

इससे ठीक एक दिन पहले, सोमवार को भी प्रधानमंत्री ने सुभाषित के माध्यम से सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा था, सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही देश आगे बढ़ता है। यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। इसके साथ ही उन्होंने एक श्लोक, समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ भी साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि हम सबके संकल्प एक समान होने चाहिए, हमारे मन एकता के भाव से जुड़े होने चाहिए, जिससे हम सभी परस्पर सहयोग तथा समान व्यवहार के साथ समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इन संदेशों के जरिए प्रधानमंत्री लगातार समाज में सकारात्मक सोच और सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

अमूल्य योगदान दिया

प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी इसी तरह का प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया था। तब उन्होंने उन सभी देशवासियों को हृदय से नमन किया था, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया।

प्रेरणा का स्त्रोत बन रहे हैं

उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है और सद्भावना तथा एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को सशक्त करने का आग्रह किया था। इस अवसर पर साझा किया गया श्लोक था, उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति॥ जिसका हिंदी अर्थ है कि परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प तथा नवाचार विकसित होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह श्लोक मनुष्य को भाग्य के भरोसे न बैठकर साहस, कर्मठता और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्य का निमार्ता है। प्रधानमंत्री के ये सुभाषित सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन रहे हैं।

एमपी और छत्तीसगढ़ की दूरी होगी अब और कम...

इन जिलों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल से जबलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और आगे जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक सिक्सलेन कॉरिडोर के निर्माण की वृहद योजना बना रही है, जिस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

वेब वार्ता, रायपुर

इस नए कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा मार्ग के जरिए रायपुर से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के आकार लेने के बाद रायपुर से भोपाल के बीच का यात्रा समय घटकर करीब-करीब आधा रह जाएगा।

रायपुर-जबलपुर के बीच का सफर भी होगा बेहद तेज

वर्तमान में रायपुर से भोपाल की सड़क यात्रा में यात्रियों को लगभग 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, वहीं रायपुर से जबलपुर पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। नए सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे के बनने से मौजूदा मार्गों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा और दोनों राज्यों की राजधानियों तथा प्रमुख शहरों के बीच सफर का समय काफी कम हो जाएगा। इस पूरी परियोजना के अंतर्गत भोपाल से सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा तक सड़क का निर्माण व अपग्रेडेशन किया जाना है। जबलपुर से छत्तीसगढ़ की सीमा (चिल्फी घाट) के बीच मौजूदा मार्ग को सिक्सलेन में तब्दील करने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित किया गया है।

डीपीआर और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी शुरू

इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (उढफ) तैयार करने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण और निर्माण एजेंसी के चयन की प्रशासनिक कार्रवाई जल्द आगे बढ़ाई जाएगी। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही परियोजना की सटीक लागत, अंतिम रूट अलाइनमेंट और निर्माण पूरा होने की समय-सीमा पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा

माल परिवहन में तेजी

- नया कॉरिडोर बनने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों के बीच माल की आवाजाही तेज होगी।

पर्यटन को गति

- रायपुर और आसपास के रहवासियों के लिए कान्हा-किसली नेशनल पार्क पहुँचना अधिक सुगम हो जाएगा। वहीं भोपाल व जबलपुर से आने वाले पर्यटकों को भी छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थलों तक आने के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी।

कर्नाटक और अहमदाबाद में 22 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के द्वारा वेटनरी अधिकारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक और अहमदाबाद में 22 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बेंगलुरु कार्यालय द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत चलाए गए तलाशी अभियान में केपीएससी कार्यालय, निलंबित चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार और सदस्य शांता होसमनी के आवास, बिचौलियों, चयनित उम्मीदवारों और मूल्यांकन एजेंसी एडुटेस्ट सॉल्यूशंस के दफ्तर शामिल हैं।

एक्सप्रेस-वे की मिट्टी से निकले ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के, खजाना पाने उमड़ा पूरा गांव

वेब वार्ता, मुरैना

ग्वालियर से आगरा के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण स्थल पर चांदी के सिक्के निकलने की खबर से पूरे गांव में ऐसा हड़कंप मचाया कि बच्चे, महिला, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक एक्सप्रेस-वे के लिए बिछाई गई मिट्टी को खोदने लगे। अब तक कई लोगों को चांदी के सिक्के मिलने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और सिक्कों को जब्त कर पुरातत्व विभाग के सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए।

दो दिन से कुछ युवक अकेले में करने आते थे खुदाई

मामला माता बसैया थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव का है, जहां से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है। तीन दिन पहले गांव का एक युवक इस निमार्णाधीन सड़क से गुजर रहा था, तो उसे मिट्टी में दबा चांदी का सिक्का दिखा। युवक ने सिक्का उठाया और घर चला गया। बाद में उसे समझ आया कि और भी सिक्के हो सकते है। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे दिन आया और मिट्टी को कुरेदने पर तीन-चार चांदी के सिक्के और मिल गए। दो दिन से कुछ युवक अकेले में खुदाई करने आते। मंगलवार की सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई, कि एक्सप्रेस-वे की मिट्टी से चांदी के सिक्के निकल रहे हैं।

देखते ही देखते पूरा गांव खोदाई के लिए पहुंच गया

इसके बाद देखते ही देखते पूरा गांव निर्माण स्थल पर आ गया। कोई खुरपी, कोई हंसिया, कोई लकड़ी तो कोई सरिया या अन्य सामान लेकर मिट्टी खोदने लगा। बताया गया है कि अब तक आठ से दस सिक्के ग्रामीणों को मिल चुके। चांदी के सिक्कों के लिए एक्सप्रेस-वे की खुदाई के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गए। एक वीडियों में एक युवक को चांदी का सिक्का मिलना भी दिखा जा रहा है।

कहीं और से खुदकर आई मिट्टी में निकल रहे सिक्के

माता बसैया थाना प्रभारी विवेक सिंह तोमर ने बताया कि इस बात की खबर उन्हें मंगलवार की सुबह साढ़े 10 बजे मिली। वह मौके पर पहुंचे तो कईयों लोग निमार्णाधीन एक्सप्रेस-वे की खुदाई कर रहे थे और चांदी के सिक्के होने की बात कह रहे थे। पुलिस के खदेड़ने पर ग्रामीण वहां से भाग गए। इसके कुछ देर बार पुलिस टीम वहां से लौट आई तो ग्रामीण फिर खुदाई करने लगे।

थाना प्रभारी तोमर ने बताया कि अब तक की गई पूछताछ में यहीं बताया गया है, कि एक्सप्रेस-वे के लिए जो मिट्टी डाली गई है, वह स्थानीय नहीं है। नहीं आसपास के किसी खेत की है। यह मिट्टी किसी और जगह से खोदकर लाई गई है। बताया गया है, कि जो सिक्के निकल रहे हैं उनमें साल 1913 लिखा हुआ है। चांदी के इन सिक्को को ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है, जब साल 1910 से 1930 तक राजा जार्ज पंचम ने चांदी के सिक्कों का चलन भारत में करवाया था। इन सिक्कों में 91 फीसद तक चांदी बताई जा रही है।

प्रशासन ने दिए सिक्कों की जांच के आदेश

मामला प्रकाश में आने के बाद अपर कलेक्टर कलेक्टर अश्विनी रावत ने एसडीएम रामनिवास सिंह सिकरवार को निर्देश दिए कि वह मामले की सत्यता का पता लगाएं। चांदी के सिक्के निकल रहे हैं, तो उनका जब्त कर पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए।

हार के बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी

वेब वार्ता, अमेठी

लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से हार के करीब 26 महीने बाद स्मृति ईरानी की बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में वापसी हुई है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ही उनकी नियुक्ति की खबर अमेठी पहुंची, बीजेपी कार्यकताओं में उत्साह देखने को मिला। कई जगह ढोल-नगाड़े बजाए गए और आतिशबाजी कर खुशी जताई गई।

कार्यकताओं के बीच इसे स्मृति ईरानी के राजनीतिक बनवास के खत्म होने के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेठी की सियासत में स्मृति ईरानी का नाम पिछले एक दशक से खासतौर पर चर्चा में रहा है। 2019 में राहुल गांधी को हराकर उन्होंने कांग्रेस के इस पुराने गढ़ में बीजेपी का परचम लहराया था।

हालांकि 2024 में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के हाथों 1 लाख 67 हजार 196 वोटों से हार मिली। चुनावी हार के बावजूद स्मृति ने अमेठी से अपना संपर्क नहीं तोड़ा। अब राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका को लेकर नए सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं।

पाकिस्तान में छापा, 40 चीनी समेत 258 विदेशी हिरासत में

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कथित स्कैम कॉल सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 258 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 40 चीनी और 170 वियतनामी नागरिक शामिल हैं। कार्रवाई सोमवार को राजधानी के बाहरी इलाके गुलबर्ग ग्रीन स्थित एक हाउसिंग सोसायटी में की गई, जहां कथित तौर पर विदेशी नागरिक संगठित तरीके से कॉल सेंटर चला रहे थे।

एमपी में अगले 5 साल जारी रहेगी लाडली बहना योजना...1.14 लाख करोड़ होंगे खर्च

कैबिनेट ने इन 18 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

वेब वार्ता, भोपाल

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य केंद्र नारी सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाएं रहीं। सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' को अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक निरंतर जारी रखने की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की है।

इस अति-महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों में कुल 1,14,365 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च करेगी। इसके साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 'लाडली लक्ष्मी योजना' हेतु भी 16,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यूपी के 25 शहरों में भारी बारीश, सड़कों-अस्पतालों में भरा पानी, कारें-बाइक डूबे

मध्य प्रदेश के रीवा-बालाघाट समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

वेब वार्ता, नई दिल्ली

उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान-दिल्ली समेत 14 राज्यों में मंगलवार को तेज बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज आगे बढ़ सकता है। यूपी के 25 शहरों में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। कई शहरों में सड़कों-अस्पतालों में पानी भर गया। कारें-बाइकें डूब गईं। कानपुर-उन्नाव में 500 से ज्यादा घरों में और प्रतापगढ़ में थाने में पानी भर गया।

राज्य के आठ जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेस-वे की मेरठ-प्रयागराज लेन पर करीब 10 मीटर सड़क धंस गई है। वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीन नदी में गाड़ी पलट गई। एसडीआरएफ ने गाड़ी में फंसे दो लोगों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के सतना में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है। एसडीआरएफ तैनात है और घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। आसनसोल के कई इलाकों में सड़कों पर 4-5 फीट तक पानी भर गया है। घर-कारें डूब गए हैं।

20 और 21 अगस्त को तेज होगा बारिश का दौर

मध्य प्रदेश के रीवा-बालाघाट समेत 14 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे के अंदर 4 से 8 इंच पानी गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिन तेज बारिश का दौर रहेगा। पिछले 24 घंटे में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसमी बारिश सामान्य से 9फीसदी कम है। बिहार में बारिश की संभावना जताई है। 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पटना समेत 14 जिलों में यलो अलर्ट है। बिहार में अब तक सामान्य से 41फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में 19 अगस्त से बारिश का दौर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 19 अगस्त को 10 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का ये दौर 20 और 21 अगस्त को और तेज होगा।

पांच लाख के इनामी रामदेव लोहरा समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार

गुमला। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के सबजोनल सदस्य रामदेव लोहरा उर्फ काका समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में रामदेव लोहरा, अरविंद नायक, मुनेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। रामदेव लोहरा पर झारखंड पुलिस ने पांच लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने इनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया है।

संपादकीय

वंदे मातरम पर बवाल

राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर देश भर में राजनीतिक बवाल मच गया, यह वाकई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम पर संसद के दोनों सदनों में बिल पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वंदे मातरम पर नया कानून बन गया और लागू हो चुका है, लिहाजा कानून का उल्लंघन अथवा राष्ट्रगीत को खंडित करना, उसके गायन-वादन में व्यवधान डालना आदि अपराध हैं। प्रत्येक अपराध की सजा भी निश्चित होती है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जो विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, नारेबाजी बुलंद है, वे तमाम राजनीतिक मानसिकता के उदाहरण हैं। सुदूर सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में मशाल-जुलूस निकाला गया। कश्मीर के श्रीनगर में मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और कांग्रेस के शीर्ष तीन नेताओं को माफी मांगने को कहा गया। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस नेताओं के पुतले जलाए गए। प्रधानमंत्री के चुनाव-क्षेत्र वाराणसी में डीएनए पर सवाल उठाए गए। मुंबई में अजीब नारेबाजी की गई-सीताराम कहेंगे, राधेश्याम कहेंगे। इन हिंदूवादी नारों का वंदे मातरम से क्या सरोकार है? गुजरात, मप्र, उप्र, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों के शहरों में भी बवाल मचाए गए, खासकर सोनिया गांधी को निशाना बनाया गया। कई शहरों में भाजपाई, जाहिर है, चेहरों ने सोनिया गांधी के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराईं और उन्हें प्राथमिकी बनाने के आग्रह पुलिस से किए गए। राजधानी दिल्ली में तो पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी ही दर्ज कराई गई है। शिकायतों में गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की मांगें भी बुलंद हुई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम के कथित अपमान को पाप करार दिया है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश एवं गीतकार बंकिम बाबू की आत्मा से माफी मांगने का आग्रह किया है।

भाजपा इसे भारत का अपमान चित्रित कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा को अपनी कमजोर नस थमा दी है, एक संवेदनशील मुद्दा दे दिया है, भाजपा इसे विकराल रूप देकर 2027 के विधानसभा चुनावों में भुना सकती है। अलबत्ता जेन-जी और अल्फा के मुद्दे पर भाजपा बचाव की मुद्रा में आ गई थी और देश का माहौल बदलने लगा था। दरअसल वह 15 अगस्त, देश के स्वतंत्रता दिवस, का पावन अवसर था। कांग्रेस मुख्यालय में भी परंपरागत रूप से तिरंगा फहराया जाता रहा है। चूंकि ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन-वादन कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, लिहाजा कांग्रेस मुख्यालय में भी गाया गया। उस समारोह के जो सीधे प्रसारण और वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, उनमें राष्ट्रगीत के गायन के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष खडगे और सोनिया गांधी आपस में बतियाते हुए दिखे हैं। फिर सेवादल का कर्मचारी उनके पास आया और दोनों नेताओं ने उसे अलग-अलग निर्देश दिए। सोनिया गांधी की उस दौरान की मुख-मुद्रा पढ़ी जा सकती है। वह वंदे मातरम गाए जाने से बेचैन लग रही थीं। राहुल गांधी ने भी बाएं मुड़ कर कुछ संकेत किए। बाद में वह यह कहते हुए सुने गए-हम अपना वंदे मातरम गा रहे हैं, सरकारी वंदे मातरम नहीं गाना है। यह अपना और सरकारी ह्यवंदे मातरम क्या होता है? बहरहाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो गीत 1875 में लिखा था और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में भी गाया गया, उसकी पृष्ठभूमि 1906-07 की भी है। इस गीत की उत्प्रेरक भूमिका आजादी की लड़ाई में क्या रही, 1936-37 में तत्कालीन मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर इस गीत के दो छंद ही स्वीकार किए गए और उन्हें ही गाया जाता रहा। संपूर्ण गीत में छह छंद हैं, जिन्हें अब संसद के जरिए सांगोपांग गाना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। गुलामी का वह दौर अब एक अतीत है, लिहाजा तब की व्यवस्थाओं में संशोधन करना अपरिहार्य है। वह संसद में किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत को बाधित क्यों किया गया, अनुशासन का उल्लंघन क्यों किया गया, यह खुद कांग्रेस के तीनों शीर्ष नेता ही स्पष्ट कर सकते हैं। बेशक खडगे 85 साल की उम्र में हैं, सोनिया गांधी भी 80 साल की हो चुकी हैं, यदि किसी कुर्सी अथवा पानी की जरूरत थी, तो उसका पहले से ही बंदोबस्त किया जा सकता था। खडगे संसद और बाहर खड़े होकर लंबे भाषण देते रहे हैं। फिर राष्ट्रगीत के दौरान ही हलचल क्यों जरूरी थी? उधर कांग्रेस का दावा है कि उसके हर अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया जाता रहा है। उसका कहना है कि छात्रों के आंदोलन से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा इस मसले पर राजनीति कर रही है।

विदेशी निवेश और नई डिपॉजिट स्कीम

जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से तेजी से पैसा निकालना शुरू किया और 2026 की पहली छमाही में सिर्फ छह महीनों के अंदर लगभग 30 अरब अमरीकी डॉलर देश से निकाल, बाहर ले गए, उससे भारतीय रुपए पर भारी दबाव पड़ा। इस वर्ष के प्रारंभ से, जून 2026 तक रुपया 89.5 रुपए प्रति डॉलर से गिरकर 94.18 रुपए प्रति डॉलर हो गया, यानी इसमें 5.23 प्रतिशत की गिरावट आई। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव दिया और एक्सचेंज रेट रिस्क (विनिमय दर के जोखिम) के खिलाफ करेंसी हेजिंग की लागत को स्वयं वहन करना तय किया। इस नए प्रावधान का फायदा उठाते हुए, बैंकों ने डॉलर डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को तेजी से बढ़ाया- पहले यह लगभग 3 से 4 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 3-5 साल की योग्य जमाओं (डिपॉजिट्स) के लिए 6 से 7 प्रतिशत या उससे ज्यादा कर दिया गया। अनिवासी भारतीयों ने इस पर उत्साह दिखाया और रिजर्व बैंक की स्पेशल स्वैप सुविधा के तहत विदेशी मुद्रा का अंतरप्रवाह प्रवाह सिर्फ दो हफ्तों में लगभग दोगुना हो गया।

यह 17 जुलाई को 20.718 अरब अमरीकी डॉलर था जो 31 जुलाई तक बढकर 40.816 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अकेले विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक डिपॉजिट्स का हिस्सा 36.725 अरब अमरीकी डॉलर था, और बाकी लगभग 4 अरब अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज और विदेशी बाजार ऋण से आए। एफसीएनआर में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ने में निश्चित रूप से मदद मिली है। जुलाई 2026 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार बढकर 692.9 अरब अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि मई 2026 के अंत में यह गिरकर 666.93 के निचले स्तर पर आ गया था- यानी सिर्फ दो महीनों में इसमें 25.9 अरब अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक की मौजूदा स्वैप स्कीम की खासियत यह है कि जब यह बैंकों को करेंसी जोखिम से मुक्त करती है, रिजर्व बैंक पर लगभग कोई खर्च नहीं आता। चूंकि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन है, इसलिए जब भी एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट से पैसे निकाले जाते हैं, तो वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार से भुगतान कर सकता है, यह भंडार पहले इन्हीं एफसीएनआर डिपॉजिट से बढ़ाया गया था। हम समझ सकते हैं कि जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बाहर का रुख किया तो रुपए में तेजी से अवमूल्यन प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नई स्वैप स्कीम की मदद से अनिवासी भारतीयों से बड़ी जमा प्राप्त करना संभव हो पाया।

विदेशी निवेश सही या अनिवासी भारतीयों की जमा : पिछले 26 सालों में, अगर हम एक तरफ विदेशी निवेश (जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश दोनों शामिल हैं) और दूसरी तरफ अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई कुल रकम (रेमिटेंस) की तुलना करें, तो पाते हैं कि देश को वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक कुल 1166.4 अरब अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और 295.7 अरब अमरीकी डॉलर का निवल पोर्टफोलियो निवेश प्राप्त हुआ। यानी पिछले 26 वर्षों में कुल 1462.1 अरब अमरीकी डॉलर का विदेशी निवेश देश को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर अनिवासी भारतीयों से देश में कुल 1780 अरब अमरीकी डॉलर के प्रेषण देश को प्राप्त हुए। आम तौर पर नीति-निमार्ता और आर्थिक विश्लेषक विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, ताकि घरेलू संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके और भुगतान संतुलन में लगातार बने रहने वाले घाटे से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को मिलाकर भी, तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा योगदान अनिवासी भारतीयों का है। लेकिन समझना होगा कि जहां एक ओर अनिवासी भारतीयों का योगदान, विदेशी निवेश की तुलना में कहीं ज्यादा है, विदेशी निवेश कई प्रकार से देश पर देनदारी का बोझ बढ़ाता है, जबकि अनिवासी भारतीयों के प्रेषण से अत्यंत कम देनदारी बढ़ती है, क्योंकि एक बार राशि आने के बाद, अनिवासी भारतीयों द्वारा राशि वापस ले जाने की प्रवृत्ति बहुत सीमित होती है। यदि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात करें, तो अभी तक निवल रूप से इन निवेशकों द्वारा निवल 295.7 अरब अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई, लेकिन आज इन निवेशकों के निवेश का पूंजीगत मूल्य 805.7 अरब अमरीकी डालर है। यदि रुपयों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कुल निवेश को देखा जाए तो वह 12.57 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आज उनके निवेश का कुल मूल्य 73.7 लाख करोड़ रुपए है, यानी कुल मिलाकर निवेश का लगभग 6 गुणा। बड़ी बात यह है कि पोर्टफोलियो निवेशक अपनी मर्जी से अपने निवेश को कभी भी (बिना सूचना के) ले जा सकते हैं। इसका एक लघु रूप हम वर्ष 2026 के प्रथम 6 माह में देख चुके हैं, जब पोर्टफोलियो निवेशकों ने 30 अरब अमरीकी डॉलर की राशि विदेश भेजी। चाहे व्यावहारिक रूप से यह असंभव है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर यह हो सकता है कि यदि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने समस्त स्टॉक को बेचने का निर्णय कर लें, तो यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी अधिक होगा। अब यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो ध्यान में आता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी आती है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद तो मिलते ही हैं, स्थानीय उद्योगों को भी तकनीक सुधार हेतु दबाव बनता है। साथ ही साथ देश में आंतरिक संसाधन कम होने पर भी देश में निवेश का स्तर बढ़ता है जिससे ग्रोथ तेज होती है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, जिससे भुगतान शेष की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन यह सब बातें और तर्क केवल सैद्धांतिक हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कुछ बातें जो सामान्यत: नजरअंदाज की जाती हैं, उनके निहितार्थों को समझने की जरूरत है। वास्तविकता यह है कि विदेशी कंपनियां, तकनीक के नाम पर विदेशों में उनके द्वारा विकसित तकनीक ही लेकर आती हैं। देश में उनके द्वारा शोध एवं विकास पर खर्च अत्यंत न्यून ही होता है। लेकिन जो तकनीक भी वो भारत में लाती है, उसकी बड़ी कीमत देश को रॉयल्टी और टेक्नीकल फीस के रूप में चुकानी पड़ती है।

यदि देखें तो रॉयल्टी और टेक्नीकल फीस की यह राशि निरंतर बढ़ती ही जा रही है और यह 2025-26 में 17.4 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच चुकी थी। गौरतलब है कि वर्ष 2009 तक रॉयल्टी पर कुछ अधिकतम सीमा लागू थी, जिसके 2009 में हटने के बाद यह राशि साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। हालांकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अचानक देश से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एफडीआई के मुनाफे, डिविडेंड, ब्याज, सैलरी, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस के रूप में पैसे बहिर्गमन की एक बड़ी देनदारी भी बनाता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2000-01 और 2025-26 के बीच आय का बहिर्प्रवाह 1010.4 अरब अमरीकी डालर था, जबकि इसी दौरान एफडीआई से कुल अंतर्प्रवाह 1166 अरब अमरीकी डॉलर था। आय यह बहिर्प्रवाह 2000-01 में सिर्फ 7.7 अरब अमरीकी डॉलर था और 2012-13 तक बढकर 34.4 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। 2025-26 में आय का बहिर्प्रवाह 103.2 अरब अमरीकी डॉलर था। बहरहाल, विदेश में जमा की कई राशि को भारत में लाना होगा।

डा. अश्वनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

अहंकार से विनय की ओर: शांति का मार्ग

जीवन फूलों की सेज नहीं है। यहाँ पल-पल संघर्ष है, परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं और दुःख भी हैं। एक समस्या हल होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन समस्याओं को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में सुख है तो दुःख भी है, छाया है तो धूप भी है। वास्तव में, यही जीवन का स्वाभाविक चक्र है। सच तो यह है कि मनुष्य के जीवन में समस्याएँ आती-जाती रहती हैं; आवश्यकता इस बात की है कि हम उनका सामना किस दृष्टि और मानसिकता से करते हैं। अक्सर समस्याओं के पीछे हमारी अपनी सोच और ह्यमैंह्व की भावना भी बड़ी भूमिका निभाती है। हम अपने पद, धन, ज्ञान, सफलता, सम्मान या विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमें उसी रूप में स्वीकार करें। जब कोई हमारी बात नहीं मानता, हमारी आलोचना करता है या हमें अपेक्षित महत्व नहीं देता, तो हमें दुःख, क्रोध या अपमान का अनुभव होता है। यही अहंकार का एक रूप है। अहंकार का अर्थ केवल

घमंड करना नहीं है, बल्कि अपने बारे में बनाई गई धारणाओं को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना भी है। इसलिए हमें अहंकार से लड़ने के बजाय अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। जब क्रोध आए, अपमान महसूस हो या किसी से स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा हो, तब थोड़ी देर रुककर स्वयं से पूछना चाहिए कि हमारे भीतर ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे-धीरे हमें समझ आने लगता है कि ये भाव स्थायी नहीं हैं। जब हम हर बात में स्वयं को सही साबित करने, दूसरों से तुलना करने और अपनी श्रेष्ठता दिखाने की इच्छा से मुक्त होने लगते हैं, तब मन में शांति आने लगती है। हम जीवन और लोगों को अधिक सहजता तथा वास्तविकता के साथ देख पाते हैं। अहंकार के संबंध में कहा जाता है-अहंकारः पतनस्य मूलं, विनयः प्रगतेः पन्थाः। यत्र विनयः तत्र ज्ञानं, यत्र ज्ञानं तत्र शान्तिः॥ इसका भावार्थ है कि अहंकार पतन का मूल है और विनय उन्नति का मार्ग है। जहाँ विनय है, वहाँ ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है, वहाँ शांति है। वास्तव में विनय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। विनय का अर्थ केवल नम्र होकर बोलना नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और सीखने के लिए सदैव तैयार रहना है।

विनम्र व्यक्ति अपनी सफलता पर घमंड नहीं करता और अपनी गलतियों से सीखने में संकोच नहीं करता। इसी कारण वह लोगों के बीच सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। ज्ञान होने पर भी यदि विनय नहीं है, तो ज्ञान अहंकार में बदल सकता है; लेकिन विनय के साथ ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊँचा बनाता है। विनय हमें क्रोध, अहंकार और अनावश्यक विवादों से बचाता है तथा रिश्तों को मजबूत बनाता है। पद, धन और सफलता मनुष्य को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसका विनय और व्यवहार उसे महान बनाते हैं। इसलिए जीवन में जितना ज्ञान और सफलता आवश्यक है, उतनी ही विनम्रता भी आवश्यक है। समस्याएँ जीवन का हिस्सा हैं और उनसे बचना संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब हम परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने भीतर के मैं को समझना शुरू करते हैं, तब कठिन परिस्थितियाँ भी हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। अंततः जीवन की सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के ह्यमैंह्व को समझने, अहंकार को नियंत्रित करने और विनय को अपनाने से मिलती है। यही संतुलित, सार्थक और शांत जीवन का मार्ग है।

सुनील कुमार महला
फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

भारतीय समाज में बेरोजगारी

देश की अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ रही है, किन्तु उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहे। हिमाचल में भी बेरोजगारी है। भारतीय समाज को आम तौर पर कृषि प्रधान देश के रूप में परिभाषित किया जाता है, किन्तु यह अर्धसत्य निष्कर्ष है। असल में भारतीय समाज का बहुसंख्यक भाग दस्तकार रहा है और वह कृषकों की जरूरतें पूरा करते हुए खाद्य पदार्थ सुरक्षा अपनी मेहनत के बदले में प्राप्त करता था।

लोहार, बढ़ई, तेली, जुलाहा, चर्मकार, बांसोर, नाई, धोबी, पत्थर की मूर्तियां बनाने और चिनाई का काम करने वाले, कच्ची ईंट बनाने वाले, घुमन्तु पशु पालक, भेड़ों की ऊन निकालने वाले, बाण बटाई का काम करने वाले, रंगाई-छपाई करने वाले, वूट्स स्टील बनाने वाले, और एक-एक पेशे से जुड़े हुए सहयोगी व्यवसाय करने वाले अनेक लोग रहते थे और सब एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हुए आराम की जिंदगी जीते थे। कोई बेरोजगार नहीं था। यह व्यवस्था एक दूसरे के सम्मान और स्वावलंबन की सोच पर आधारित थी, बाकी बारीकियां जो भी रही हों, हमें तो केवल यह देखना है कि देश कृषि के अलावा उत्पादक दस्तकारी पर ज्यादा निर्भर था। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की उत्पादक व्यवस्था को नष्ट करने का बीड़ा उठाया, ताकि वह अपने देश के उद्योगों में बने उत्पादों को भारत में बेच सके। क्योंकि यहां के उत्पाद गुणवत्तापूर्ण थे, इसलिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद से यह कार्य करने के रास्ते अपनाए।

कहीं समाज में व्याप्त छोटे मोटे मतभेदों को हवा देकर, तो कहीं बुनकरों के हाथ के अंगूठे काट कर सीधी कार्रवाई करके, कहीं दस्तकारों को कच्चे माल की उपलब्धता को नियंत्रित करके स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया गया। इसी के चलते ज्यादातर दस्तकारी से बेदखल हुए लोगों को कृषि का रास्ता पकड़ना पड़ा। उसमें भी स्थायी बंदोबस्त करके जागीरदारी प्रथा को कायम किया, जिससे बहुत से दस्तकारों को जागीरदारों के मजदूर काश्तकार के रूप में जीवन यापन करना पड़ा, जिससे पैदा विसंगतियां और सामाजिक टूटन आज दिन तक देश के सामने अनेक प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्याएं खड़ी करती रहती है। अब जबकि देश की आबादी भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है तो इस औद्योगिक विस्तार के मॉडल से दस्तकार समाज की खोई हुई रोजी की भरपाई कैसे हो सकेगी, यह प्रश्न लगातार चिंता को बढ़ाता ही जा रहा है। पढ़े-लिखे बच्चे पुरानी दस्तकारी तकनीकों को अपना कर वर्तमान विकसित तकनीक वाले उद्योगों से टक्कर नहीं ले सकते हैं। वर्तमान औद्योगिक मॉडल में रोजगार प्रदान करने की क्षमता बहुत सीमित है और स्वचालित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपायों से कामगारों की जरूरत को लगातार घटाया जा रहा है। ऐसे में खेती में भी सबको रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश जोतें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि उन पर पूरे परिवार का पालन संभव ही नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं, जहां 80 प्रतिशत जोतें एक हेक्टेयर से भी छोटी हैं जिनमें आधी तो 2-3 बीघे मात्र ही हैं। इतनी कम जमीन पर आदमी सम्मानपूर्वक घर-बार तो बसा सकता है और इतनी जमीन तो होनी ही चाहिए, किन्तु सम्मानजनक आय खड़ी नहीं कर सकता।

सरकारी नौकरी तो मात्र दो-तीन प्रतिशत लोगों को ही स्थापित कर सकती है। तो वर्तमान सरकारी और निजी उद्योगों की नौकरी जिसमें आईटी क्षेत्र भी शामिल है, कृषि, पशुपालन की वर्तमान स्थिति के बावजूद जो बेरोजगारों की बड़ी संख्या इंतजार में खड़ी है और हर साल बढ़ती जा रही है, उनके लिए जवाब ढूंढने की जरूरत है। लोग नौकरी के इंतजार में आयु सीमा पार कर जाते हैं, फिर हताश होकर जीवन जीने को बाध्य होते हैं। ये परिस्थितियां देश के लिए सही नहीं हैं। सरकारें कोशिश करने के तमाम दावों के बावजूद जरूरत का दस प्रतिशत भी रोजगार खड़ा नहीं कर पा रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ रही है, किन्तु उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहे। हिमाचल का उदाहरण लें तो बेरोजगारों की संख्या 6 लाख 32 हजार है (31 मार्च 2025 तक), जबकि बहुत से लोग रोजगार कार्यालय में पंजीकरण को फिजूल मान कर पंजीकरण ही नहीं करवा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि असली आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। हिमाचल में पिछले तीन साल में सरकारी नौकरी 23 हजार 200 लोगों को दी गई। निजी क्षेत्र में 51 हजार को इस अवधि में नौकरी मिली। अत: प्रतिवर्ष 24 हजार 733 लोगों को नौकरी मिली। तो इस दर से 6 लाख 32 हजार लोगों को नौकरी मिलने में 25 वर्षों से ज्यादा समय लगेगा। तब तक और कितने बेरोजगार इसमें जुड़ जाएंगे, यानी यह अनंत इंतजार का खेल है। धन्य है हमारे राजनेताओं को, जो इतनी साफ तस्वीर होने के बावजूद लोगों को पीछे लगाए रखते हैं और सच नहीं बोलते। जो बोलेगा वह जाएगा। यानी हम आम नागरिक भी सच सुनना ही नहीं चाहते। न योजना बनाने वाला और न लाभार्थी, जब दोनों ही सच सुनने को तैयार नहीं तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। सभी जब सफेद कॉलर जॉब ढूंढेंगे तो कैसे संभव होगा। तीन उंगली से कागज तो लिखे जाते हैं, जरूरत की वस्तुएं तो पैदा नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि मशीनीकरण से संभव होगा, किन्तु मशीनीकरण ने ही तो रोजगार छीने हैं। सौ छीन कर दस पैदा किए हैं तो 90 प्रतिशत का घाटा कैसे पूरा होगा? हम यूरोप और अमरीका की ओर समाधान के लिए देखने लगते हैं। किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि इन देशों ने उपनिवेशवादी दौर में विकासशील देशों की जो लूट की थी, यह उसी के ऊपर खड़ी इमारत है। उतनी बुनियादी पूंजी हमें कहां से मिलेगी। फिर आजकल चीन का उदाहरण देने और उससे सीखने की बहुत बात होती है। किन्तु हम कभी चीन नहीं बन सकते।

चीन साम्यवादी सरकार चलाने वाला घोर पूंजीपति देश बन चुका है। भले ही उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष चाहने वाले उसे इस रूप में देखने का साहस नहीं कर पाते, किन्तु सच्चाई तो यही है। चीन ने 1978 में ही आर्थिक उदारीकरण की राह पकड़ ली थी, जबकि भारत में उदारीकरण 1991 में शुरू हो सका। तब तक चीन, अमरीका के स्वार्थों का लाभ उठा कर अमरीका की ही सहायता से दुनिया का उत्पादन केंद्र बन गया। अब तो अमरीका भी अपनी चीन संबंधी नीति को गलत मान रहा है क्योंकि वह अमरीका का ही प्रतिस्पर्धी बन गया है। हर देश अपनी शक्ति और सामयिक हालात को देख कर बनाई योजना और रणनीति से ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें किसी की घटिया नकल बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति और सीमाओं को देख कर समाधान ढूंढने चाहिए। औद्योगिक नीति को विकेन्द्रित करना होगा।

कुलभूषण उपमन्यु
पर्यावरणविद

आलेख

वंदेमातरम क्यों बना राजनीतिक विवाद का विषय?

वंदेमातरम केवल दो शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों, राष्ट्रभक्ति की भावना और उस दौर के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके गायन से देशभक्ति से वातावरण भी गुंजायमान हो जाता है। जिस गीत ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जगाने में भूमिका निभाई, वह आज राजनीतिक बहस और विवाद का विषय बन गया है। सवाल यह नहीं है कि वंदेमातरम् का सम्मान होना चाहिए या नहीं—उसका सम्मान भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निर्विवाद रूप से होना चाहिए। असली सवाल यह है कि आखिर एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत को बार-बार राजनीतिक विवाद के केंद्र में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? अभी १५ अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में फिर से इसको लेकर विरोधियों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। यानी देशभक्ति को भी तराजू में तोला जा रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह सह नहीं है। आज देश ८० वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। आगामी दिवस जब २१ साल बाद देश १०० वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा तब भी हम देश को उंचाइयों पर ले जाने की जगह यह विवाद कर रहे होंगे। आज के राजनेताओं को देश के लिए कुछ सोचना होगा।

भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधाराएं सदियों से साथ-साथ रही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन ने भी इसी विविधता को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में जोड़ने का काम किया था। वंदेमातरम् उसी दौर की राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण स्वर था। इसलिए जब इसे राजनीतिक बयानबाजी का हथियार बनाया जाता है, तो केवल एक गीत पर विवाद नहीं होता, बल्कि उस व्यापक राष्ट्रीय भावना पर बहस खड़ी हो जाती है, जिसने देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट किया था। वंदेमातरम् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में सामने आया। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे उत्साह और संघर्ष की भावना के साथ अपनाया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों में इसके उद्घोष ने लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा की। यही कारण है कि वंदेमातरम् को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। लेकिन इतिहास के साथ-साथ उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज था। राष्ट्रवादी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए यह आवश्यक था कि देश के सभी समुदायों को उसमें बराबर का स्थान महसूस हो। वंदेमातरम् के कुछ अंशों की धार्मिक प्रतीकात्मकता को लेकर समय-समय पर आपत्तियां भी सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने 1937 में यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक अवसरों पर गीत के शुरूआती दो पदों का उपयोग किया जाए, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य माना गया। यह निर्णय बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व ने भी राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया था। स्वतंत्र भारत में भी वंदेमातरम् को विशेष सम्मान मिला। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान देने की बात स्वीकार की। वहीं जन गण मनङ को राष्ट्रगान और वंदेमातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यानी भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय जीवन में दोनों की अपनी विशिष्ट पहचान बनी। समस्या तब पैदा होती है, जब इस ऐतिहासिक संतुलन को राजनीतिक बहस में बदलकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन अधिक राष्ट्रवादी है और कौन कम।

राष्ट्रभक्ति किसी एक गीत, नारे या प्रतीक तक सीमित नहीं हो सकती। देश के प्रति सम्मान का अर्थ संविधान के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कर्तव्यों का पालन और राष्ट्रहित में ईमानदार योगदान भी है। यदि कोई व्यक्ति वंदेमातरम् का सम्मान करता है तो यह उसकी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति को केवल इस आधार पर मापना कि वह किसी विशेष अवसर पर किस तरह का नारा लगाता है, लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, यह भी सही है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना समाज में बनी रहनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय गीत या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीक का जानबूझकर अपमान करना भी उचित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। इसलिए वंदेमातरम् के सम्मान और उसके राजनीतिक दुरुपयोग—दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा। आज राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इतिहास को समझें, उसे चुनावी हथियार न बनाएं। वंदेमातरम् पर बहस यदि इतिहास, साहित्य, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हो तो वह सार्थक हो सकती है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल विरोधी दल या किसी समुदाय को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए किया जाए तो यह बहस समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करेगी। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है—क्या राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भावनात्मक नारों तक सीमित हो जाना चाहिए? यदि देश में बेरोजगारी है, किसान अपनी आय को लेकर चिंतित है, युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में है, सीमाओं की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है, शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और गरीब व्यक्ति सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना भी राष्ट्रभक्ति है। सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, किसान खेत में अन्न पैदा करता है, शिक्षक नई पीढ़ी तैयार करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और श्रमिक अपने श्रम से अर्थव्यवस्था को गति देता है। इन सभी के योगदान में राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है।

दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक बहस में कई बार वास्तविक मुद्दों की जगह प्रतीकों को केंद्र में लाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। प्रतीकों की अपनी भूमिका है, लेकिन प्रतीक तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे की भावना और जिम्मेदारी को भी समझा जाए। वंदेमातरम् का मूल संदेश मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से जुड़ा है। यदि हम इस भावना को समझ लें तो विवाद अपने आप छोटा हो सकता है। यह भी विचार करने की जरूरत है कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान स्वाभाविक होना चाहिए, राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं। देशभक्ति को आदेश से पैदा नहीं किया जा सकता। वह नागरिक के मन में इतिहास, शिक्षा, संस्कार और देश के प्रति अपनेपन की भावना से विकसित होती है। जब राष्ट्रप्रेम को राजनीतिक पहचान की कसौटी बना दिया जाता है, तब लोकतांत्रिक समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होना स्वाभाविक है।

वंदेमातरम के संदर्भ में राजनीतिक दलों को भी संयम दिखाना चाहिए। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद किसी एक दल की संपत्ति नहीं है। विपक्ष को भी यह समझना होगा कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रतीकों को केवल राजनीतिक विरोध के लिए खारिज करना उचित नहीं है। दोनों पक्षों को इतिहास के प्रति सम्मान और वर्तमान के प्रति जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान बहुस्तरीय है। इसमें वंदेमातरम है, जन गण मन है, तिरंगा है, संविधान है और स्वतंत्रता आंदोलन की असंख्य स्मृतियां हैं। इसमें शहीदेआजम भगत सिंह का साहस है, महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, सुभाषचंद्र बोस का संघर्ष है, सरदार पटेल की एकता की भावना है और डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित संवैधानिक लोकतंत्र की दृष्टि भी है। भारत को इनमें से किसी एक प्रतीक में सीमित नहीं किया जा सकता।

वंदेमातरम पर विवाद खड़ा करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि क्या हम उस भारत की भावना को समझ रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था? वह भारत ऐसा था जिसमें विभिन्न समुदायों ने मिलकर विदेशी शासन का मुकाबला किया। स्वतंत्रता का संघर्ष किसी एक जाति, धर्म या भाषा का संघर्ष नहीं था। वह पूरे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था। आज आवश्यकता इस बात की है कि वंदेमातरम् को विवाद का विषय बनाने के बजाय इतिहास और राष्ट्रीय चेतना के सम्मान के रूप में देखा जाए। जहां सम्मान आवश्यक है, वहां सम्मान हो; जहां संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, वहां संविधान सर्वोपरि हो; और जहां राजनीतिक मतभेद हों, वहां लोकतांत्रिक संवाद हो।

वंदेमातरम का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके नाम पर समाज में दूरी नहीं, बल्कि देश के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो। राजनीति को राष्ट्रभावना से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्रभावना को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और उसकी लोकतांत्रिक परंपरा का मूल संदेश भी यही है कि असहमति के बावजूद देश सबसे ऊपर रहे। इसलिए समय आ गया है कि वंदेमातरम को लेकर होने वाली बहस नारों की राजनीति से ऊपर उठे। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा जाए, राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान दिया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से समझा जाए। आखिरकार राष्ट्र केवल गीतों और नारों से नहीं बनता—राष्ट्र नागरिकों के विश्वास, संविधान की मयार्दा, सामाजिक सद्भाव और करोड़ों लोगों के ईमानदार योगदान से बनता है। वंदेमातरम् पर बहस हो तो भारत को जोड़ने के लिए हो, बांटने के लिए नहीं। यही उस गीत की ऐतिहासिक भावना के प्रति सच्चा सम्मान होगा।

लेखक - सौरभ वार्ष्णेय
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।)

संक्षिप्त वार्ता

आयुर्वेद से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में सोमवार को चरक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा और एआईआईए के निदेशक प्रो. वैद्य पीके प्रजापति समेत संस्थान के अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। विभागाध्यक्ष प्रो. महेश व्यास ने डॉ. जोशी का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जोशी ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगों से बचाव, स्वास्थ्य संवर्धन और बेहतर जीवनशैली का भी विज्ञान है। उन्होंने स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आयुर्वेद को अपनाने पर जोर दिया।

डीएसईयू ने शुरू किया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दाखिला

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) में विभिन्न डिप्लोमा, स्नातक, बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में खाली सीटों पर दाखिले के लिए वॉक-इन प्रवेश शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों अभ्यर्थी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दाखिला ले सकेंगे।

अभ्यर्थी एक सप्ताह तक डीएसईयू मुख्यालय, द्वारका सेक्टर-9 के कमरा नंबर 122 में दोपहर दो से शाम पांच बजे के बीच पहुंचकर मौके पर पंजीकरण, सीट आवंटन और फीस जमा कर सकते हैं। दाखिला केवल उपलब्ध खाली सीटों के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ लाने की सलाह दी है। पंजीकरण और प्रवेश शुल्क ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से जमा करना होगा।

डीयू में सभी रेगुलर कोर्स में दाखिला की अंतिम तिथि 31 अगस्त

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कई कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटें अभी खाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रेगुलर कोर्स में दाखिले की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में विद्यार्थियों को इस तारीख तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अधिसूचना में स्नातकोत्तर, पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ, बीटेक, एमटेक (माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन), जीएटी-बी 2026, स्नातक, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन और एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल हैं। यानी इन कार्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर 31 अगस्त के बाद दाखिले की गुंजाइश नहीं रहेगी, जब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई अलग निर्णय या विस्तार जारी नहीं किया जाता।

बारापुला फ्लाईओवर का काम इस माह हो जाएगा पूरा

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। बारापुला फ्लाईओवर के तीसरे चरण का निर्माण कार्य इसी माह पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के पूरा होने से दक्षिण-पूर्वी दिल्ली से नोएडा की ओर आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और सराय काले खां, मयूर विहार सहित आसपास के इलाकों में लगने वाले जाम की समस्या भी कम होगी।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि मयूर विहार फेज-एक के पास बारापुला फ्लाईओवर के लूप को नोएडा की ओर यूपी लिंक रोड फ्लाईओवर के कैरिजवे से जोड़ने का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लूप और यूपी लिंक रोड फ्लाईओवर के बीच एक्सपेंशन जॉइंट डालने और उसे समतल करने का काम किया जा रहा है। यह काम भी आधे से अधिक पूरा हो चुका है। इस लूप के जरिए बारापुला फ्लाईओवर सीधे लिंक रोड फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा। जिससे सराय काले खां, एम्स की ओर से बारापुला के रास्ते नोएडा जाने वालों को सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि सफेद पट्टियों की मार्किंग, ध्वनि अवरोधक लगाने और यातायात संबंधी बोर्ड लगाने का काम किया जा चुका है। सराय काले खां की ओर इस पर चढ़ने वाले रास्ते के शुरूआती स्थान को फिनिशिंग देने का काम किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जॉइंट एक्सपेंशन का काम पूरा होते ही फ्लाईओवर को पूरी तरह यातायात के लिए तैयार माना जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से फ्लाईओवर के औपचारिक उद्घाटन की तिथि तय किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि प्रदूषण में कमी और ईंधन की बचत में मदद मिलेगी।

दिल्ली को कूड़े से आजादी के लिए एमसीडी की कार्ययोजना तैयार

दफ्तरों से बाजारों तक चलेगा विशेष सफाई अभियान

राजधानी को कूड़े और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान-2026 की कार्ययोजना तैयार की है। 17 अगस्त से शुरू हुआ अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इसके तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के साथ सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पार्कों, जलाशयों और कूड़ा जमा होने वाले स्थानों की विशेष सफाई कराई जाएगी।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

कार्यालयों में लंबे समय से पड़े अनुपयोगी सामान और पुराने रिकॉर्ड को हटाकर कबाड़ निस्तारण पर भी जोर दिया जाएगा। कार्ययोजना के अनुसार सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड कक्ष, भंडार कक्ष, गलियारों, शौचालयों, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की सफाई होगी। पुराने दस्तावेजों की छंटाई कर नियमों के तहत निस्तारण किया जाएगा। खराब फर्नीचर, पुराने उपकरण और अन्य अनुपयोगी सामान भी हटाए जाएंगे।

दोबारा कूड़ा जमा होने वाले स्थानों पर विशेष नजर

अभियान के दौरान ऐसे स्थानों को चिह्नित किया जाएगा, जहां सफाई के बाद बार-बार कूड़ा जमा होता है। इनकी विशेष सफाई के साथ दोबारा गंदगी न होने देने के उपाय किए जाएंगे। बाजारों, पार्कों, जलाशयों, झुग्गी बस्तियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सप्ताहांत में विशेष अभियान चलेगा। जरूरत के अनुसार नालियों की गाद निकालने के साथ अवैध पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाएंगे। पेड़ों की छंटाई, पौधारोपण और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के काम भी होंगे। अधिकारी और कर्मचारी श्रमदान करेंगे। सरकारी कार्यालयों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखने तथा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

कबाड़ और अनुपयोगी सामान भी हटाया जाएगा

सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में बनेंगी 3 नई आवासीय कॉलोनियां

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में 3 नई आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं के तहत पुराने सरकारी आवासीय परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास तैयार किए जाएंगे।

उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग में करीब 70 एकड़ क्षेत्र में पुराने सरकारी क्वार्टरों का पुनर्विकास किया जाएगा। यहां सरकारी आवासों के साथ निजी खरीदारों के लिए भी आवास और व्यावसायिक परिसर विकसित किए जाएंगे। परियोजना में 90 प्रतिशत हिस्सा आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा जाएगा।

पूर्वी दिल्ली के कल्याणवास में करीब 32 एकड़ क्षेत्र में आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। यहां भी 90 प्रतिशत आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक निर्माण प्रस्तावित है।

जलभराव वाली सड़कों पर समस्या दूर करने को कारणों की होगी तलाश

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। बरसात में सड़कों पर जलभराव के कारण तलाश कर उनको दूर करने का काम किया जाएगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बार 65 सड़कों पर बारिश में जलभराव की समस्या चिह्नित की है

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीडब्ल्यूडी व नगर निगम से ऐसे स्थानों की जानकारी साझा कर समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए लिखा है। इन एजेंसियों ने ट्रैफिक पुलिस को भरोसा दिलाया है कि वह जल्द कारण तलाश कर समाधान करेंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिन पहले उपराज्यपाल को बैठक में अवगत कराया था कि इस वर्ष मानसून में 65 स्थानों पर जलभराव की शिकायत प्राप्त हुई हैं। इन स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित होता है। साथ ही दावा किया था कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम समेत अन्य एजेंसियों के सक्रिय प्रयास के चलते पिछले वर्ष की तुलना में जलभराव की समस्या 61 प्रतिशत कम हुई। वर्ष 2025 में ऐसे 169 स्थान चिह्नित किए गए थे। इस वर्ष जलभराव वाले स्थानों की रिपोर्ट दूसरी एजेंसियों से साझा कर सुधार के स्थायी कदम उठाने को कहा गया है। इन स्थानों में गाजीपुर मुर्गा मंडी, पांडव नगर अंडरपास, बुराड़ी मेन रोड, साउथ गणेश नगर, संजय टी-पॉइंट, जनपथ, एमबी रोड, एमबी रोड एसडीएम ऑफिस, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, मंदिर मार्ग, झरोदा स्टैंड, शकूरबस्ती अंडरपास, मायापुरी चौक, दिल्ली गेट, रिंग रोड पर वाई पॉइंट, ईदगाह गोल चक्कर समेत कई मार्ग शामिल हैं।

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि वह अपनी सड़कों पर जलभराव की समस्या दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जिन सड़कों पर पानी भरता है, उसके कारणों का पता किया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टा जलभराव के छोटे-छोटे कारण समझ आते हैं। जिनमें नाले-नालियों के ढलान में खामी, ड्रेन होल में कचरा जैसी समस्या नजर आती है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर रोक के खिलाफ केवाईएस की आवाज

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अनुमति नहीं दिए जाने और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पत्र लिखा है। संगठन ने नागरिकों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और अपनी बात रखने के मौलिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। केवाईएस के अनुसार, शास्त्री भवन क्षेत्र में धारा 163 लागू होने का हवाला देकर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। संगठन का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे छात्रों और युवाओं को हिरासत में लिया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। संगठन ने दावा किया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के मोबाइल फोन भी ले लिए। संगठन ने महिलाओं समेत प्रदर्शनकारियों को देर रात रिहा किए जाने पर भी आपत्ति जताई। केवाईएस ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए इसे गंभीर विषय बताया।

राजधानी में खुले पशुओं का बढ़ता आतंक, स्कूल-पार्क से बाजार तक दहशत

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर खुले घूम रहे गाय, कुत्ते और बंदर लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। कहीं सड़क के बीच बैठी गाय यातायात बाधित कर रही हैं तो कहीं कुत्तों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं। लुटियन दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन के आसपास भी बंदरों की मौजूदगी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। कई इलाकों में बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों में इन पशुओं को लेकर भय का माहौल है। शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं।

राजधानी के पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा गांव में भी खुले पशुओं की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में हर माह करीब 10 से 12 लोग आवारा पशुओं की चपेट में आ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक परेशानी बंदरों और आवारा कुत्तों से है। लोगों का कहना है कि बंदर और कुत्ते कई बार स्कूलों और पार्कों में अचानक झुंड के साथ पहुंचकर लोगों पर हमला कर देते हैं। इससे बच्चों, छात्रों और बुजुर्गों में डर बना हुआ है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव के बाहर से गुजरने वाले विकास मार्ग और उससे जुड़ी सड़कों पर दिल्ली नगर निगम ने कूड़ेदान रखे हैं। इन कूड़ेदानों के आसपास कूड़ा बिखरा रहने के कारण गाय और अन्य पशु बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। कई बार सड़क पर पशुओं के बैठने और घूमने के कारण विकास मार्ग पर यातायात प्रभावित होता है और लंबा जाम लग जाता है। लोगों का कहना है कि वाहनों के लगातार आवागमन और हार्न से परेशान होकर कई बार पशु अचानक वाहन चालकों की ओर बढ़ जाते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति अधिक जोखिमपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निगम पार्षद मोनिका पंत और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों और बंदरों को पकड़ने के लिए नियमित दल गांव में नहीं पहुंचते। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों से बंदरों को हटाने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण खुले पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और समस्या अब केवल यातायात तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ गई है। कड़कड़डूमा गांव निवासी अजय ने बताया कि पार्कों में कूड़ा पड़ा रहने के कारण गाय, बंदर और कुत्ते वहां पहुंचते हैं। इससे पार्क में आने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कई बार कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं और समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। जुगल किशोर के अनुसार, बेसहारा गाय अक्सर सड़कों पर 15 से 20 के झुंड में बैठती हैं। ऐसे में उन्हें हटाना मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि कई बार गायों के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और पशुओं के अचानक आक्रामक होने से लोग चोटिल तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने कहा कि गांव में गाय, बंदर और कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनके अनुसार, कुछ समय पहले उन्हें भी कुत्ते ने काट लिया था।

बच्चों ने चित्रों में उकेरा मेरा भारत-एकता में विविधता का संदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ओर से नानकपुरा स्थित कार्यालय में बच्चों के लिए ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय मेरा भारत-एकता में विविधता रखा गया। बच्चों ने रंगों और कल्पना के जरिए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता का संदेश दिया।

स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मंगलवार को आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में कक्षा एक से पांच, दूसरी में कक्षा छह से 10 और तीसरी श्रेणी में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करते हुए देश की एकता, विविधता और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े चित्र बनाए। बच्चों की पेंटिंग में देशभक्ति के साथ ही अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों के बीच आपसी सौहार्द का संदेश भी देखने को मिला। प्रतियोगिता के समापन पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं, प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को उनकी भागीदारी के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर दिया

पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्रता दिवस से जोड़ने के साथ उनमें देशभक्ति, समावेशिता और ह्यएकता में विविधताह्ण की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम ने बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के जरिए देश के प्रति भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी दिया।

न्याय की मांग कर रहे विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया: आप

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार को कथित तौर पर दिल्ली पुलिस की ओर से मंगलवार तड़के हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाते हुए उसपर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाये हैं।

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सुबह चार बजे सादे कपड़ों में पहुंची दिल्ली पुलिस कुलदीप कुमार को उनके आवास से अपने साथ ले गई। उनके आवास पर लगें सीसीटीवी को तोड़ दिया और डीवीआर साथ ले गई। केजरीवाल ने कहा कि अब उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एक विधायक को बिना किसी जानकारी और कारण पुलिस घर से उठा कर ले जा सकती है तो इस देश में आम आदमी कहां जाए। वही, आप के बुराड़ी से विधायक संजीव झा मंगलवार को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से कुलदीप कुमार के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि कुलदीप कुमार को किस मामले में और कहां ले जाया गया है। संजीव झा ने आरोप लगाया कि कल्याणपुरी में एक सफाई कर्मचारी की हत्या के मामले में न्याय की मांग करने के कारण कुलदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंचे और उनकों अपने साथ ले गई।

जल उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में पूरी छूट

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार ने घरेलू और गैर-घरेलू जल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया पानी के बिलों पर 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी की योजना की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। भाजपा शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने इसे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बताते हुए योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

दीपक गाबा ने कहा कि योजना के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड को वास्तविक बकाया राशि की वसूली में मदद मिल रही है और उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिल रही है। उनके अनुसार अब तक 5.27 लाख उपभोक्ता इस छूट योजना का लाभ उठा चुके हैं और 3,261 करोड़ रुपये का विलंब शुल्क माफ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के दायरे में 14.09 लाख घरेलू और 70,312 वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं। समय-सीमा बढ़ाए जाने से पुराने बकाया पानी के बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क से पूरी राहत पाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। गाबा ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मूल बकाया राशि जमा करने पर मिलने वाली विलंब शुल्क माफी की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुराने पानी के बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से अपील की कि वे 31 मार्च 2027 तक योजना का लाभ उठाकर मूल बकाया राशि जमा करें और विलंब शुल्क में पूरी छूट प्राप्त करें।

दिल्ली की सड़कों के विदेशी नाम बदलने की मुहिम

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ने दिल्ली की कुछ सड़कों के विदेशी नाम हटाकर भारतीय गौरवशाली व्यक्तित्वों के नाम पर रखने की मांग उठाई है। पार्टी अध्यक्ष प्रताप चंद्रा ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेजकर नाम परिवर्तन की मांग की है।

प्रताप चंद्रा ने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम ऐसे लोगों के नाम पर होने चाहिए, जिन्होंने समाज और देश के लिए निःस्वार्थ योगदान दिया हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद कर उनसे प्रेरणा ले सकें। पार्टी का दावा है कि दिल्ली की 32 सड़कों के नाम अभी भी ऐसे विदेशियों के नाम पर हैं, जिन्होंने भारत पर शासन और शोषण किया था। पार्टी ने इन 32 सड़कों की सूची के साथ उनके स्थान पर नाम दिए जाने वाले 32 भारतीय गौरवशाली व्यक्तित्वों की सूची भी पत्र के साथ भेजी है।

प्रताप चंद्रा ने कहा कि स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद दिल्ली की सड़कों के नाम भारतीय इतिहास और गौरव से जुड़े महान व्यक्तित्वों के नाम पर किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए योगदान देने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से याद करना उनके योगदान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पार्टी ने गृह मंत्रालय और संबंधित प्रशासन से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सामाजिक हित में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

विकसित भारत शिक्षक पुरस्कार के लिए नामांकन की समय-सीमा बढ़ी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। सेंटर फॉर नमो स्टडीज ने विकसित भारत शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 अगस्त की रात तक कर दी है। समय-सीमा बढ़ाए जाने से देशभर के शिक्षकों को शिक्षण और राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस राष्ट्रीय पहल में भाग लेने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। पुरस्कार समारोह 3 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया जाएगा।

राघव चड्ढा का भाजपा की नई टीम में नाम नहीं, मंत्रिमंडल में जगह की अटकलें तेज

नई दिल्ली, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां मिलने के बाद अब राघव चड्ढा को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा की हालिया नई राष्ट्रीय टीम में राघव चड्ढा का नाम शामिल नहीं होने के बाद चर्चा है कि उन्हें संगठन के बजाय केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने के संकेतों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है।

कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी राजनीतिक टूट के दौरान राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर भाजपा का रुख किया था। इस घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी के लिए अब तक की बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक माना गया। इसके बाद भाजपा ने संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी देकर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। संदीप पाठक को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में राघव चड्ढा के अगले कदम को लेकर चर्चा बढ़ गई है। इससे पहले भी यह कयास लगाए जाते रहे हैं कि युवा नेता के रूप में राघव चड्ढा को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में करीब 3 दर्जन नेताओं की नियुक्ति के बावजूद उनका नाम सामने नहीं आने को इसी संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने की बात

कही थी। उनके इस बयान के बाद उन नेताओं को लेकर भी अटकलें तेज हुई हैं, जिन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों से सांसदों को भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ लाने में भूमिका निभाई है।

राघव चड्ढा की दावेदारी पर क्यों हो रही चर्चा

राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिना जाता रहा है। पेशे से चार्टर्ड लेखाकार रहे राघव चड्ढा ने राज्यसभा में युवाओं, कामगारों और विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और सार्वजनिक मंचों पर प्रभावी वक्तव्य देने की क्षमता के कारण उन्हें पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में माना जाता रहा है। आम आदमी पार्टी में लंबे समय से चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच राघव चड्ढा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा के साथ जाने के घटनाक्रम में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया। यही वजह है कि अब उनके लिए केंद्र सरकार में संभावित जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है।

हालांकि, राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इसलिए मंत्रिमंडल में उनकी संभावित नियुक्ति को फिलहाल राजनीतिक अटकल के रूप में ही देखा जा रहा है। भाजपा ने संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी में वह संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

संदीप पाठक की संगठन क्षमता को देखते हुए भाजपा में उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने को महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। पंजाब सहित उन राज्यों में उनकी भूमिका अहम हो सकती है, जहां भाजपा आगामी चुनावों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

संक्षिप्त वार्ता

थाना प्रभारी से मुख्यमंत्री तक लगाई गुहार, फिर भी नहीं खुला रास्ता

वेब वार्ता/हरदोई। मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम मझियाई जाफरपुर में दबंगों द्वारा आबादी के पुराने रास्ते को दीवार खड़ी कर बंद किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजपाल सिंह का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित के अनुसार 24 जुलाई को राजस्व व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाया था, लेकिन 11 अगस्त की रात आरोपितों ने कथित रूप से तीन दीवारें खड़ी कर फिर रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। डायल-112 पर सूचना के बावजूद निर्माण नहीं रुकने का पीड़ित ने दावा किया है। राजपाल सिंह का कहना है कि वह थाना प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आहत पीड़ित ने चेतावनी दी है कि रास्ता कब्जामुक्त नहीं कराया गया तो वह जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करेगा। उसने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

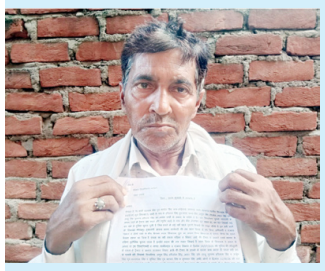

सवारियों को कार में लिफ्ट देकर लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

फिरोजाबाद, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। थाना फरिहा पुलिस ने सोमवार रात मुठभेड़ के बाद सवारियों को कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार घायल आरोपी गजेंद्र पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

थाना फरिहा के प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार के अनुसार, 11 अगस्त को फिरोजाबाद के शांति नगर, थाना रसूलपुर निवासी गौरव ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। गौरव ने पुलिस को बताया कि वह यमुना एक्सप्रेसवे के कुबेरपुर क्षेत्र में खड़े होकर गौतमबुद्ध नगर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार वहां आकर रुकी।

पांच वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काटा

लोनी, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। लोनी क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में गली में खेल रही पांच वर्षीय मासूम के चेहरे पर कुत्ते ने काट लिया। परिजन उसे संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर कुत्ते काटने का टीका लगाया। अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले मौसीन की बहन आसमां पांच वर्षीय पुत्री कशिश के साथ मायके आई हुई है। उन्होंने बताया कि बहन की बेटी सोमवार को गली में खेल रही थी। इस दौरान गली में घूमने वाले कुत्ते ने उसके चेहरे पर काट लिया। उसके शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोगों ने कुत्ते का भगाया। परिजन उसे संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे।

चिकित्सक ने मासूम का प्राथमिक उपचार कर कुत्ते काटने का टीका लगाया। मौसीन ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक है। अधिकारियों को गलियों में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाना चाहिए। संयुक्त अस्पताल के प्रभारी डॉ. कैलाश चंद ने बताया कि कुत्तों के हमलों में वृद्धि हुई है। अस्पताल में रोजाना 35 से अधिक लोगों को कुत्ते काटने के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।

मुनाफे का झांसा दे दस करोड़ से अधिक ठगे

गाजियाबाद, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। कारोबार में मुनाफे का झांसा देकर राजनगर एक्सटेंशन निवासी व्यक्ति से दस करोड़ रुपये से अधिक की रकम ठगने का मामला सामने आया है। नंदग्राम पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआईपी एड्रेसेस सोसाइटी में रहने वाले संदीप गोयल के मुताबिक उनकी मुलाकात नोएडा सेक्टर-22 निवासी रवि राणा से हुई थी। रवि ने उन्हें बड़े कारोबारियों के बारे में बताया, जो व्यापार में रुपये लगाकर भारी मुनाफा कमाते हैं। आरोप है कि उसे 15 से 20 प्रतिशत तक लाभ देने का भरोसा दिया गया। शुरूआत में 10 से 20 लाख रुपये लिए गए और निर्धारित समय पर रकम वापस कर दी गई। इससे उनका आरोपियों पर विश्वास बढ़ गया। संदीप गोयल के मुताबिक मई 2023 के आसपास करोड़ों रुपये निवेश करने की बात कही गई। उन्होंने उस व्यक्ति से मिलवाने को कहा, जिसके कारोबार में रकम लगाई जानी थी। इसके बाद रवि उन्हें रोहिणी ले गया। वहां उसकी मुलाकात रेनू चौहान से कराई गई। रेनू ने खुद को अमवे कंपनी में डायमंड प्लस स्तर पर काम करने वाली बताया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच भी पारिवारिक संबंध बन गए। पीड़ित का कहना है कि वह रेनू के भाई सौरभ चौहान की शादी में भी परिवार सहित शामिल हुए थे। आरोप है कि रेनू और उसके साथियों ने ऑक्टा फॉरेक्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग और अमवे के कारोबार में निवेश कराने की बात कही। 40 से 50 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच दिया गया और उन्हें 15 से 20 प्रतिशत लाभ देने का भरोसा दिलाया।

छात्रावासों में अव्यवस्थाओं पर डीएम सख्त, निरीक्षण में लगाई फटकार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने मंगलवार को बावन रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास में कई अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने छात्रों से बातचीत कर भोजन, साफ-सफाई, शौचालय, बिजली, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली।

छात्रावास की रसोई में बेहद खराब साफ-सफाई और गंदगी मिलने पर जिलाधिकारी ने वार्डन अतुल श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई तथा तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य कविता त्रिपाठी को छात्रावास की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी और स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान प्रकाश व्यवस्था में कमी मिलने पर बल्ब और लाइट की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। बिजली के खुले तारों को तत्काल ठीक कराने, खिड़कियों में जाली लगवाने तथा दरवाजों को व्यवस्थित कराने को भी कहा गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं के दुरुस्तीकरण एवं आवश्यक कार्यों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश भी दिए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने परिसर में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। शौचालय, साफ-सफाई समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी छात्रावासों में साफ-सफाई, गुणवत्तापूर्ण भोजन, विद्युत, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

इसके बाद डीएम ने जीआईसी परिसर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालक का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां साफ-सफाई में लापरवाही मिलने पर सफाई कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोऑपरेटिव मेस संचालित कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि छात्रावासों में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण में मिली कमियों को तत्काल दूर कराया जाए और भविष्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद सदर तहसील में रजिस्ट्री पर लगा ब्रेक, आईजीआरएसयूपी वेबसाइट ठप

गाजियाबाद, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। गाजियाबाद सदर तहसील में मंगलवार दोपहर से मकान और भूखंड की रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो गया। रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होने वाली आईजीआरएसयूपी वेबसाइट अचानक बंद होने के कारण तहसील पहुंचे खरीदार और विक्रेताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। वेबसाइट के काम नहीं करने से पहले से निर्धारित कई रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

दोपहर से वेबसाइट में तकनीकी समस्या आने की जानकारी सामने आई। इसके बाद रजिस्ट्री से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया रुक गई। निर्धारित समय पर तहसील पहुंचे लोगों को वेबसाइट दोबारा शुरू होने का इंतजार करना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि रजिस्ट्री के लिए पहले से समय निर्धारित था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उन्हें बिना काम पूरा हुए इंतजार करना पड़ा। वेबसाइट बंद होने का असर तहसील में रजिस्ट्री का काम कर रहे कर्मचारियों पर भी पड़ा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण दस्तावेजों से संबंधित आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। कर्मचारियों को भी वेबसाइट के दोबारा चालू होने का इंतजार करना पड़ा।

रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि वे निर्धारित समय पर सभी आवश्यक तैयारी के साथ तहसील पहुंचे थे, लेकिन वेबसाइट ठप होने के कारण उनका समय और संसाधन दोनों प्रभावित हुए। मंगलवार शाम तक वेबसाइट के दोबारा शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। विशेष रूप से उन खरीदारों और विक्रेताओं को अधिक दिक्कत हुई, जिनकी रजिस्ट्री के लिए पहले से तारीख और समय तय था।

गाजियाबाद में दो महिलाओं समेत चार पर ठगी का मुकदमा

गाजियाबाद, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआईपी सोसाइटी में रहने वाले संदीप गोयल ने दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ निवेश के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा नंदग्राम थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी एमवे और अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश कराने के नाम पर पिछले करीब चार वर्षों से उनसे लगातार रकम लेते रहे। पीड़ित के मुताबिक, शुरूआत में आरोपियों ने उन्हें करीब 10 लाख रुपये का लाभ दिलाया, जिससे उनका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग कंपनियों में निवेश के नाम पर बड़ी रकम लगवानी शुरू कर दी। आरोप है कि हरियाणा और दिल्ली से जुड़े आरोपियों ने उन्हें कई व्यापारियों और उद्योगपतियों से भी मिलवाया, ताकि निवेश को भरोसेमंद दिखाया जा सके।

गाजियाबाद के पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात, ड्यूटी भत्ता 600 रुपये हुआ

परिवार सहित 5 लाख रुपये की नकदरहित चिकित्सा सुविधा

पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित रही। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की नकदरहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस सुविधा से स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या उपचार की स्थिति में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पीआरडी स्वयंसेवकों की सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।

गाजियाबाद, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की नकदरहित चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया गया। लखनऊ में बहुमंजिला बैरक के निर्माण की आधारशिला रखने की घोषणा भी की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, रामगढ़ ताल से प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए सीधा सम्मेलन आयोजित किया गया। गाजियाबाद में भी पीआरडी स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सुना।

ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब उन्हें ड्यूटी के लिए प्रतिदिन 600 रुपये मिलेंगे, जबकि इससे पहले यह राशि 500 रुपये थी। इस बढ़ोतरी से प्रदेशभर में ड्यूटी करने वाले पीआरडी स्वयंसेवकों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। स्वयंसेवकों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से अपेक्षित मांगों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बहुमंजिला बैरक की आधारशिला रखने की भी घोषणा की।

सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने पर जोर

विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। विवेकानन्द सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड तथा निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग की खराब प्रगति से जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी अधिकारी अपने विभाग की रैंकिंग पर विशेष ध्यान देते हुए सुधार के लिए प्रभावी प्रयास करें।

उन्होंने संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा जिन बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनमें तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास सहित निमार्णाधीन परियोजनाओं की जानकारी ली गई।

डीएम ने अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपडेट रखें।

सीडीओ ने किया छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण

व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति राजकीय बालिका छात्रावास मन्नापुरवा एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने परिसर में नियमित साफ-सफाई कराने, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने तथा सभी तलों पर डस्टबिन रखवाने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिए। निरीक्षण में तीनों छात्रावासों में लगे अग्निशमन यंत्रों की गैस समाप्त मिली। इस पर उन्होंने तत्काल उनकी रिफिलिंग कराने और स्टोर रूम में रखी निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण कराने को कहा।

उन्होंने छात्रावास परिसर की खाली भूमि पर किचन गार्डेन विकसित करने तथा बाउंड्री के किनारे शोभाकारी एवं फलदार पौधे लगवाने के निर्देश भी दिए। तीनों छात्रावासों में फर्स्ट एड किट उपलब्ध न मिलने पर तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा गया। सीडीओ ने छात्रावासों में रह रहे बालक-बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानीं। विद्यार्थियों ने मैस संचालन और लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। इस पर सीडीओ ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रावास अधीक्षकों और विद्यार्थियों से समन्वय स्थापित कर मैस अथवा टिफिन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षका सुषुमा देवी, अर्चना विश्वकर्मा, छात्रावास अधीक्षक सौरभ कुमार तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव मौजूद रहे।

जैविक खेती परियोजना को प्रभावी ढंग से संचालित कर कृषकों को अधिकाधिक लाभ दिलाएं : मुख्य विकास अधिकारी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जैविक खेती परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की प्रगति, कृषकों की सहभागिता, जैविक फसलों के उत्पादन, प्रशिक्षण तथा जैविक निवेशों की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि बिलग्राम, माधौगंज एवं मल्लावां विकासखंडों के 19 राजस्व ग्रामों में जैविक खेती परियोजना संचालित है। इसके तहत 1,690 कृषक जुड़े हैं तथा करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 50 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। कृषकों को जैविक खेती की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण देने के साथ एक्सपोजर विजिट भी कराई जा रही हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जैविक खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखते हुए उत्पादों की गुणवत्ता, प्रमाणन, विपणन और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य एवं नीमास्त्र जैसे जैविक निवेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इनके उपयोग की सही विधि का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि परियोजना की गतिविधियों का नियमित स्थलीय सत्यापन कर किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और अधिक से अधिक कृषकों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण, मृदा की उर्वरता बनाए रखने और किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

बैठक में उपनिदेशक कृषि डॉ. राजेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र, परियोजना समन्वयक डॉ. राजीव कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कूड़ा डालने का विरोध पर महिला से अभद्रता

मोदीनगर, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। गांव सीकरी कला में रहने वाली अंजू शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पड़ोसी अक्सर नाली में कूड़ा भर देते हैं। आरोप है कि पिछले दिनों विरोध पर आरोपियों ने महिला और उसकी बेटियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। पुलिस का कहना है कि मामले में रमाकांत और उनके पुत्र भविष्य वशिष्ठ उर्फ भानु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

कंडौहुना में जलभराव और बदहाल सड़कों पर भड़के सपा नेता, आंदोलन की चेतावनी

वेब वार्ता। लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 18 अगस्त। हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रामज्ञान गुप्ता ने गांव कंडौहुना पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने हरसंभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि मामूली बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या के स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगर की अधिकांश सड़कें जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नघेटा रोड, मेडिकल कॉलेज, आरआर इंटर कॉलेज व बाल विद्या भवन जाने वाले मार्गों के अलावा मन्नापुरवा के निकट लखनऊ मार्ग, बिलग्राम चुंगी, गुरुगुज्जा, राधानगर, इंदिरानगर, हरीपुरवा, चांद बेहटा, मंगली पुरवा

रोड, मिल रोड, आवास विकास कॉलोनी, आशा नगर, सुभाष नगर, आजाद नगर, कृष्णानगरिया, देविनपुरवा, कौशलपुरी और सर्कुलर रोड पर भी जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क, नाला-नाली और जलनिकासी के लिए आने वाले बजट का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण जनता को हर वर्ष इसी समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सोमवार को कंडौहुना रोड पर जलभराव के कारण ई-रिक्शा पलटने से कई लोग घायल हुए, जबकि एक मासूम बच्चे का पैर टूट गया।

उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द जलनिकासी और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी सड़क और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।

इस दौरान समाजवादी व्यापार सभा के जिला महासचिव अवनीश यादव, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव दीपू, आकाश यादव, ठाकुर अंकित सिंह, श्याम गुप्ता, शुभम गुप्ता, सोनू गुप्ता, कपिल, रिंकू राजवंशी, राकेश, रविशंकर, आशीष, शिवम, उमेश, सुभाष, मुकेश, बालकराम, सौरभ, नन्हे, प्रिंस, निखिल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

राम मंदिर दान चोरी

चंपत के साथ अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट

लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में दोनों के नाम शामिल नहीं हैं। अब रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, अंतिम रिपोर्ट में केवल उन आठ आरोपियों के नाम हैं, जिन्हें मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सबसे ज्यादा आरोप लगे थे। दबाव बढ़ने के बाद दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी मामले की जांच अभी जारी रखे हुए है।

मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली टीम में आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार शामिल थे। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चोरी की पुष्टि हुई थी। करीब 80 लाख रुपये की बरामदगी पुलिस को सूचना दिए बिना किए जाने की बात भी सामने आई थी। 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। इसके बाद 25 जून को आठ लोगों के खिलाफ श्रीराम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज किया गया। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अज्ञात आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार कर्मचारियों को नकदी छिपाकर ले जाते हुए दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। जांच में ट्रस्ट और बैंक की संयुक्त मानक कार्यप्रणाली का पालन नहीं होने तथा प्रवेश-निकास पर तलाशी की व्यवस्था न होने का भी उल्लेख था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी को जांच तेजी से पूरी कर सही निष्कर्ष तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद भक्तों के दान के प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

कावेरी जल विवादः तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा-

तय हिस्से से ज्यादा पानी मिल चुका

नई दिल्ली। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि उपलब्ध आंकड़ों को कुल मिलाकर देखने पर ऐसा लगता है कि तमिलनाडु को उसके निर्धारित हिस्से से अधिक पानी मिल चुका है।

तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कर्नाटक को अपने हिस्से का पानी तत्काल जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का कहना था कि कम बारिश वाले साल में उसे कावेरी से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और इससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। तमिलनाडु ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की अनुशंसित मात्रा और कर्नाटक से वास्तविक रूप से मिल रहे पानी को अपनी जरूरतों से कम बताया।

कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि कावेरी बेसिन में पानी की भारी कमी है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमिलनाडु को अब तक 14.814 टीएमसी पानी मिल चुका है। उनका कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों और अनुपात के आधार पर पानी की उपलब्धता का आकलन किया जाना चाहिए। दीवान ने यह भी बताया कि कर्नाटक ने आने वाले दिनों में कम पानी की भरपाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पानी छोड़ने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

दोनों पक्षों से फैक्ट शीट, एक सप्ताह बाद सुनवाई

दोनों राज्यों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पानी की उपलब्धता और आपूर्ति से संबंधित फैक्ट शीट पेश की। पीठ ने कहा कि उसने दोनों दस्तावेजों की जांच की है और मामले को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। अगली सुनवाई में अदालत के सामने यह स्पष्ट किया जाएगा कि दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रवाह और निर्धारित हिस्से की स्थिति क्या रही।

दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा- छात्रों पर कार्रवाई जरूरी थी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक या गैरकानूनी बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुआ प्रदर्शन शुरूआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में बैरिकेड तोड़ने और प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने की कोशिश के बाद स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि भीड़ के नियंत्रण से बाहर होने के बाद हालात संभालने के लिए चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल

8वां वेतन आयोगः पुराने पेंशनर्स को झटका या मिलेगी राहत?

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की मांगें भी तेज हो गई हैं। खासतौर पर 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन को लेकर पेंशनर्स संगठनों ने सरकार से स्पष्ट प्रावधान करने की मांग की है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है। अब आयोग की परामर्श प्रक्रिया अहम चरण में पहुंच चुकी है।

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने खत्म की भूख हड़ताल

रांची। झारखंड सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद, 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल का अनशन देर रात रांची में मंत्रियों की उपस्थिति में समाप्त हुआ। रांची सदर अस्पताल में झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी देर रात पहुंचे। उन्होंने छात्र नेता देवेंद्र महतो को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इसके बाद देवेंद्र महतो अस्पताल से सीधे अपने घर चले गए। साथ ही प्रदर्शनकारी हबीबा और राहुल का भी अनशन समाप्त कराया गया।

भूख हड़ताल तोड़ने के बाद देवेंद्र महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज, हमारी 16 दिनों की भूख हड़ताल सम्मानजनक तरीके से समाप्त हुई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे और हमारे विधायक जयराम महतो की संयुक्त पहल से हमने यह फैसला लिया। जिन मांगों के लिए

हम संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, वे सभी पूरी हो गई हैं। प्रदर्शनकारी हबीबा ने सरकार की सराहना करते हुए कहा, हमारी सरकार ने साबित कर दिया है कि यह आदिवासियों, मूलवासियों और सदनों की सरकार है और यह उनके हितों के बारे में सोचती है। आज हमें यह एहसास हुआ है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हेमंत हैं, तो हिम्मत है।

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के प्रदर्शनकारियों ने भी परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंच छात्रों के हित में यह ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पुष्टि की कि देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया और उन्होंने ही उन्हें जूस पिलाया जिसके बाद उनका अनशन समाप्त हो गया। इरफान अंसारी ने इस फैसले का श्रेय राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया। उन्होंने कहा, यह मुख्यमंत्री का एक ऐतिहासिक निर्णय था। राहुल गांधी ने हमें निर्देश दिया और एक पत्र लिखा, जिसके बाद सरकार ने युवाओं की मांगों को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उनकी कोशिशें रंग लाईं, जिसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग बहुत कठिन थी और आमतौर पर कोई भी सरकार ऐसी मांग को नहीं मानती। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत उदारता दिखाई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में छात्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से सुधारों की मांग की गई थी।

छात्रों के आगे झुकी सरकार, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द

रांची। झारखंड सरकार ने लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने परीक्षा रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में हुई छोटी-बड़ी गड़बड़ियों और अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने का भी निर्णय लिया है। फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए पहले से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है। यदि उसका सही तरीके से पालन किया जाता तो कई गड़बड़ियों को रोका जा सकता था। अब सुधारों में जरूरी बदलाव जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधनों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द बैठक कर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र के संशोधनों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी और परीक्षा व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

छात्र नेता ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया

जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन में सहयोग करने वाले छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों का आभार जताया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को भी छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए धन्यवाद दिया। महतो ने कहा कि जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है और अनियमितताओं में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए कथित गिरोहों के पीछे मौजूद मुख्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। सरकार की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने राहत जताई और अनशन समाप्त करने की बात कही।

26/11 हमले के छह पाकिस्तानी आरोपियों पर चलेगा गैरहाजिरी में मुकदमा, सईद और लखवी भी आरोपी

मुंबई। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में मौजूद छह फरार आरोपियों के खिलाफ अब उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपियों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित हैंडलर हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी के अलावा साजिद मीर, अबू अलकामा, आसिम उर्फ अबू काहफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा शामिल हैं। विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 लागू होने के बाद किसी आतंकी मामले में गैरहाजिरी में मुकदमा चलाने की यह पहली प्रक्रिया होगी। बीएनएसएस की धारा 356 फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है, ताकि आरोपी के फरार रहने के कारण न्यायिक प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक लंबित न रहे। मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को पत्र लिखकर छह फरार आरोपियों के खिलाफ गैरहाजिरी में मुकदमा शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया था। पुलिस का कहना है कि 26/11 हमले जैसे गंभीर मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और कानून के अनुसार उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए बीएनएसएस की धारा 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निकम ने विशेष अदालत में आवेदन देकर बताया कि ये सभी 26/11 मामले में वांछित आरोपी हैं। जांच के दौरान गिरफ्तार आतंकी अजमल कसाब ने भी पूछताछ में इन आरोपियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी थी।

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण विवाद गहराया, सीएम उमर ने चेताया

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल (एल-जी) द्वारा आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी देने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है और जेन-जी प्रोटेस्ट जैसे विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। उनकी कैबिनेट ने 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन उपराज्यपाल की मुहर का इंतजार है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा खत्म होने से पहले, सरकारी नौकरियों में विभिन्न वर्गों के लिए 43 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं, जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोग, पिछड़े इलाकों के निवासी, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक शामिल थे।

लेकिन 2024 में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन कर सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 43प्रतिशत से बढ़ाकर 70प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ोतरी पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने के कारण हुई थी, जिसका गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने हमेशा विरोध किया। गुर्जरों को शांत करने के लिए प्रशासन ने एसटी कोटा 10 से बढ़ाकर 20प्रतिशत करने की घोषणा की। इस फैसले से वे समूह नाराज हो गए जो किसी भी आरक्षण के दायरे में

नहीं आते थे, क्योंकि उनके लिए केवल 30प्रतिशत नौकरियां ही बची थीं। इस पृष्ठभूमि में, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आरक्षण को 50प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की। एक कैबिनेट सब-कमेटी ने अक्टूबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और अगले ही महीने उपराज्यपाल आवास (लोक भवन) भेज दिया। हालांकि, उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल उठाए थे, जिनका जवाब सरकार ने दे दिया है, लेकिन उसके बाद से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा, उसके बाद क्या हुआ, कोई हमें बताए। क्या इसे मंजूरी मिल गई है? उम्मीद है कि ह्यजेन-जीह्ल वाला ट्रेंड यहां भी नहीं फैलेगा। इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हमने अपना काम कर दिया हैह्व यह अच्छी बात नहीं है कि वे हमारी कैबिनेट के प्रस्तावों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं या उन्हें दबाए हुए हैं। उन्होंने प्रशासन पर कैबिनेट के प्रस्तावों को दबाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भी उबाल ला दिया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसे दलों ने आरक्षण को तर्कसंगत बनाने का वादा किया है। वहीं, बीजेपी ने अग्निवीरों और आरक्षित समूहों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का वादा किया है। उमर अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के भीतर और जनता से भी विरोध का सामना करना पड़ा है, खासकर तब जब विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू में रिजर्वेशन कैटेगरी के ज्यादा सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। फिलहाल, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर यह गतिरोध जारी है।

सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, सत्ता में बैठे लोगों से नागरिक सवाल पूछें

कोलकाता। रिटायर आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि देश में बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा। इसके लिए नागरिकों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने होंगे और मजबूत समुदाय बनाने होंगे। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने नेताओं से नियमित रूप से टाउन हॉल बैठकें करने की भी अपील की। बेदी गोलपार्क स्थित रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में आयोजित अमृता डागा मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने और उनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

बेदी ने कहा कि नेताओं को हर एक-दो महीने में टाउन हॉल बैठकें आयोजित करनी चाहिए, ताकि वे सीधे जनता की समस्याएं सुन सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों को विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, खासकर नई पीढ़ी को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अवसर मिलना जरूरी है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों के लिए ईमेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत भी बताई। बेदी ने कहा कि जब नेता वोट मांगने के दौरान जनता की सेवा का वादा करते हैं, तो नागरिकों को उनसे उनके काम और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी समस्याएं सामने नहीं रखेंगे तो समाधान की उम्मीद भी कम हो जाएगी।

मीरा भयंदर में मुंबई मेट्रो का गिरा स्लैब गिरा

मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीर भयंदर में मुंबई मेट्रो की निमार्णाधीन लाइन 9 से ग्रेनाइट का एक स्लैब गिर गया है, इस हादसे में एक स्कूल वैन बाल-बाल बची है। हालांकि स्लैब गिरने से गिरे मलबे की वजह से स्कूल वैन के टायर पंचर हो गए। इसके बाद सडक पर काफी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। यह घटना सोमवार सुबह करीब 11.50 बजे हुई, जब मेदेतिया नगर मेट्रो लाइन 9 (दहिसर से मीरा भायंदर) का निर्माण कार्य चल रहा था।

अभिजीत दीपके को एनडीए में आने का मिला ऑफर

मोदी सरकार में मंत्री ने कहा- हम स्वागत करेंगे

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख रामदास आठवले ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि, दीपके की ओर से इस प्रस्ताव पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दीपके और सीजेपी फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात कह रहे हैं।

आठवले ने सोमवार को कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सपने को पूरा करने तथा समाज और पार्टी को मजबूत करने के लिए दीपके को आरपीआई(ए) में शामिल होना चाहिए। दीपके ने हाल ही में राजनीति में तत्काल प्रवेश से इनकार किया था। उन्होंने हालांकि कहा था कि यदि बड़ी संख्या में लोग चाहेंगे तो वह भविष्य में इस पर विचार कर सकते हैं। जनता की मांग होने पर चुनाव लड़ने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है।

सीजेपी ने जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की अगुवाई की थी। अगस्त के पहले सप्ताह में संगठन ने राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन किया, लेकिन स्पष्ट किया कि फिलहाल इसे

राजनीतिक दल में नहीं बदला जाएगा। संगठन का कहना है कि वह चुनावी राजनीति में उतरने के बजाय जमीनी स्तर पर काम और जनजागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देगा। दीपके ने भी कहा है कि भारत में एक और राजनीतिक पार्टी बनाना फिलहाल समाधान नहीं है। हालांकि, उन्होंने भविष्य में जनता की मांग के आधार पर अपनी भूमिका बदलने की संभावना खुली रखी है।दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव से ह्यस्कूल ठीक करोह्ल अभियान की शुरूआत की है।

उन्होंने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। उन्होंने निजी स्कूलों की फीस सीमित करने की भी मांग की। दीपके के मुताबिक, अभियान के तहत स्कूलों में पानी, खिड़कियां, बेंच और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति का आंकड़ा जुटाया जाएगा। इसके लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसके जरिए स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अगले चरण में महाराष्ट्र के अन्य तालुकों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया जाएगा। सीजेपी ने राजस्थान के स्कूलों में भी अभियान चलाने की योजना बताई है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

रायपुर नॉर्थ जोन में एसीपी पंडरी कार्यालय और विशेष न्यायालय का शुभारंभ

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के नॉर्थ जोन में पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई पहल की गई है। नॉर्थ जोन अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में सहायक पुलिस आयुक्त पंडरी कार्यालय और विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पंडरी न्यायालय का शुभारंभ किया गया। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप ने दोनों कार्यालयों का विधिवत शुभारंभ किया। नई व्यवस्था से पंडरी और खमतराई थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस से संबंधित कार्यों के बेहतर समन्वय की उम्मीद है। हाल ही में कृष्ण कुमार चंद्राकर को सहायक पुलिस आयुक्त पंडरी के पद पर पदस्थ किया गया है। उनकी पदस्थापना के बाद अब एसीपी पंडरी कार्यालय का विधिवत संचालन शुरू हो गया है। इससे पहले एसीपी उरला पूर्णिमा लामा अतिरिक्त प्रभार के रूप में एसीपी पंडरी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। नए कार्यालय के शुरू होने के बाद पंडरी और खमतराई थाना क्षेत्र सीधे एसीपी पंडरी के पर्यवेक्षण में रहेंगे। इन क्षेत्रों में दर्ज आपराधिक मामलों की विवेचना की गुणवत्ता बेहतर करने, अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर और त्वरित पुलिसिंग उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना स्तर पर होने वाली कार्रवाई और जांच की लगातार निगरानी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, कल होगा सीट और महाविद्यालय का आवंटन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत आयोजित की जा रही है।प्रथम चरण की काउंसलिंग 5 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक हुई है। असफल फीस ट्रांजेक्शन वाले अभ्यर्थियों के लिए पुनः फीस जमा करने की प्रक्रिया 16 अगस्त को की जाएगी। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 18 अगस्त को ऑनलाइन पंजीयन करने वाले अभ्यर्थियों को पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। 20 से 22 अगस्त तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने के लिए 20 से 23 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। यह उल्लेखनीय है कि पीएटी काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है। सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग के लिए 20 से 24 अगस्त 2026 तक (रात्रि 11:30 बजे) ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

राजधानी से रोजगारधानी की ओर बढ़ता नवा रायपुर, टेक्सटाइल पार्क हजारों रोजगार का नया केंद्र

औद्योगिक निवेश से रोजगार का नया आधार बन रहा नवा रायपुर अटल नगर

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर अब केवल आधुनिक प्रशासनिक राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक अधोसंरचना के साथ शहर में ऐसे उद्योगों को आकर्षित किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकें। नवा रायपुर में टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे भविष्य के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के इन प्रयासों का उद्देश्य केवल नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना नहीं, बल्कि विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करना भी है। नवा रायपुर के लेयर-2 स्थित ग्राम कुर्रू में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना के लिए सीएसआईडीसी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की शुरुआत अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। स्विफ्ट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2026 में 235 करोड़ रुपए के निवेश से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमिपूजन किया है। इस इकाई से करीब 4,650 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं पुनीत क्रिएशन के साथ 175 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं को मिलाकर टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस तरह टेक्सटाइल पार्क नवा रायपुर में विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

132 एकड़ में फार्मा पार्क, स्वास्थ्य उद्योग को मिलेगी नई गति

स्वास्थ्य और औषधि निर्माण के क्षेत्र में भी नवा रायपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेक्टर-22 में 132

एकड़ भूमि ष्टस्ढ्ढष्ठष्ट को आवंटित की गई है, जहां फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 1,400 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों टोरेंट फार्मा, एविला फार्मास्युटिकल्स और विटालिस हेल्थ के साथ कुल 735 करोड़ रुपए के एमओयू किए जा चुके हैं। फार्मा पार्क के विकसित होने से दवा निर्माण के साथ इससे जुड़ी विभिन्न औद्योगिक और सहायक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी बढ़ते कदम

भविष्य की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। नवा रायपुर ने इस क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यश फैंस ने 110 करोड़ रुपए के निवेश से होम अप्लायंसेज निर्माण इकाई शुरू की है। यह निवेश नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण निर्माण के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (ष्टस्नष्ट) को भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। यहां क्क्षष्टक्च प्रोटोटाइपिंग, 3ष्ठ प्रिंटिंग और श्वरूष्ट टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एमएसएमई बनेंगे औद्योगिक विकास की रीढ़

नवा रायपुर के औद्योगिक विकास की कहानी केवल बड़े निवेशों तक सीमित नहीं है। बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को भी मजबूत आधार दिया जा रहा है। सेक्टर-05 में विनिर्माण उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की गई है। यहां वर्तमान में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि भविष्य में 12,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय उद्यमिता और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ बड़े उद्योगों के लिए सहायक औद्योगिक नेटवर्क विकसित होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

निवेश से रोजगार और रोजगार से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार

नवा रायपुर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर बताती है कि शहर के विकास का अगला चरण प्रशासनिक राजधानी से आगे बढ़कर निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में आकार ले रहा है। टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10,000 रोजगार, फार्मा पार्क में करीब 1,400 रोजगार और स्न्स्ल्ध क्षेत्र में भविष्य में 12,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं—ये सभी मिलकर नवा रायपुर की अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में विकसित हो रहा इकोसिस्टम नवा रायपुर की औद्योगिक संभावनाओं को और व्यापक बना रहा है। शहर में 2,000 सीटों वाला प्लग एंड प्ले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जहां Square Business Services, Vrize India और Vision Plus जैसी आईटी कंपनियां कार्य कर रही हैं।नवा रायपुर में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू सेक्टर आधारित औद्योगिक क्लस्टरों का विकास है। टेक्सटाइल के लिए अलग क्षेत्र, फार्मा के लिए समर्पित पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की शुरुआत और स्न्स्ल्ध के लिए औद्योगिक भूमि—ये प्रयास शहर की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान कर रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक सेवाओं के विकास की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सपरिवार किया रुद्राभिषेक

रायपुर। श्रावण मास के तृतीय सोमवार के पावन अवसर पर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सपरिवार देवाधिदेव महादेव की आराधना की। उन्होंने विधि-विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रदेशवासियों के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। खासकर सावन सोमवार पर शिवालयों में भगवान महादेव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने की परंपरा है। इसी धार्मिक परंपरा

का निर्वहन करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। पूजन के दौरान भगवान महादेव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद सांसद अग्रवाल ने भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर जनकल्याण की कामना की।

प्रमोद दुबे ने दिव्यांग बच्चों को भेंट की श्रवण मशीनें

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर स्थित अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में रोटरी एलिगेंस की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण के बाद स्कूल के दो श्रवण बाधित बच्चों को उच्च स्तरीय श्रवण मशीनें भेंट की गईं। कार्यक्रम में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद रोटरी एलिगेंस की टीम ने दो बच्चों को आधुनिक श्रवण मशीनें प्रदान कीं। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि इन मशीनों का उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों को सुनने में सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके संवाद और सीखने की क्षमता को विकसित करने में मदद मिल सके। स्कूल में करीब 75 बच्चे अध्ययनरत हैं।

अदाणी पावर छोटे भंडार में हर्षोल्लस के साथ मनाया 80 वां स्वतंत्रता दिवस

रायगढ़। अदाणी पावर लिमिटेड (APL), छोटे भंडार में देश का 80वाँ स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्लांट के अधिकारी एवं कर्मचारी, उनके परिवारजन तथा आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ चीफ बिजनेस ऑफिसर (CBO) एवं प्रोजेक्ट हेड द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। अपने संबोधन में CBO ने राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका, सुरक्षित कार्य संस्कृति, विश्वसनीय विद्युत उत्पादन तथा स्थानीय समुदाय के विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रोजेक्ट हेड ने 2×800 मेगावाट परियोजना की प्रगति की जानकारी साझा करते हुए क्षेत्र में संचालित विभिन्न सीएसआर एवं सामुदायिक विकास पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदाणी पावर स्थानीय समुदायों के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके बाद उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सुरक्षा विभाग के 26 कर्मचारियों को सम्मानित

किया गया। साथ ही प्लांट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 19 कर्मचारियों को स्पॉट रिकग्निशन अवॉर्ड प्रदान किए गए।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा

समारोह में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (ASDC) एवं सिलाई केंद्र के प्रशिक्षुओं ने देशभक्ति गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

प्राथमिक शाला आमलीभौना एवं कोटमारा के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं अदाणी पावर ग्रीन हार्मनी लेडीज क्लब की सदस्यों ने देश के विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति एवं पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देकर भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुंदर झलक प्रस्तुत की।

प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविता पाठ एवं संगीत प्रस्तुत कर समारोह को विशेष बना दिया। उनकी प्रस्तुतियों को उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।कार्यक्रम के समापन अवसर पर CBO एवं प्रोजेक्ट हेड ने सभी प्रतिभागी बच्चों, प्रशिक्षुओं एवं लेडीज क्लब की सदस्यों को उपहार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में मिष्ठान वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ।

प्रभा फाउंडेशन द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉ. आकांक्षा साहू को स्मृति चिन्ह से सम्मान किया

रायपुर। प्रभा फाउंडेशन रायपुर के द्वारा समाज में सशक्त कार्य करने वाले स्वास्थ्य शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मान समारोह दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन रविवार को विमतारा शंकर नगर रायपुर के आयोजन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह अध्यक्षता रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुण्ड रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा नगर निगम के महापौर मिलन चौबे के गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ

सम्मान समारोह में स्वास्थ्य एवं शिक्षा नशा मुक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के जन जागृति कार्य को देखते हुए डॉ आकांक्षा साहू स्व्ब्क्र स्न प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू महासभा का सम्मान स्मृति चिन्ह श्रीफल से शाल श्रीफल से सम्मान किया गया अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का करने वाले को भी सम्मान किया गया

कार्यक्रम के आयोजक प्रभा फाउंडेशन एवं द्विवेदी होम्योपैथी के संस्थापक डॉ विद्याकांत द्विवेदी डॉ उपेंद्र द्विवेदी डॉ उत्कर्ष द्विवेदी द्वारा संपन्न

हुआप्रभा फाउंडेशन द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉ आकांक्षा साहू को स्मृति चिन्ह से सम्मान किया

प्रभा फाउंडेशन रायपुर के द्वारा समाज में सशक्त कार्य करने वाले स्वास्थ्य शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मान समारोह दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन रविवार को विमतारा शंकर नगर रायपुर के आयोजन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह अध्यक्षता रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुण्ड रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा नगर निगम के महापौर मिलन चौबे के गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ

सम्मान समारोह में स्वास्थ्य एवं शिक्षा नशा मुक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के जन जागृति कार्य को देखते हुए डॉ आकांक्षा साहू स्व्ब्क्र स्न प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू महासभा का सम्मान स्मृति चिन्ह श्रीफल से शाल श्रीफल से सम्मान किया गया अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का करने वाले को भी सम्मान किया गया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के निधन पर जताया शोक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रमेश शर्मा ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

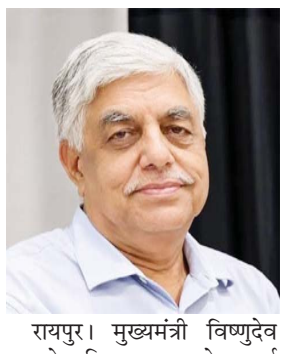

2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग

शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पदोन्नति में विसंगतियों और लंबित स्थानीय समस्याओं को लेकर शिक्षक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ और सर्व शिक्षक संघ के पदाधिकारी शामिल रहे। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सेवा सुरक्षा और पदोन्नति से जुड़े विषयों पर स्पष्ट और व्यावहारिक निर्णय लिया जाना जरूरी है। ताकि वर्षों से शासकीय स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगों में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करना शामिल है। शिक्षक संगठनों ने मांग की कि राज्य शासन NCTE के समन्वय से हर साल कम से कम दो बार विशेष ञ्जश्वञ्ज का आयोजन करे। इससे सेवा में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे और उनकी सेवा सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। शिक्षक संगठनों ने वर्ष

2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी राहत की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त शिक्षकों को ञ्जश्वञ्ज की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए। पदोन्नति को लेकर भी शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर पात्र शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और ञ्जश्वञ्ज उत्तीर्ण करने के लिए 1 सितंबर 2028 तक पर्याप्त समय दिया जाए। इससे शिक्षकों की वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। मार्च 2026 में जारी पदोन्नति सूची और इसके बाद 11 अगस्त 2026 को जारी आदेश को लेकर भी शिक्षकों ने आपत्ति जताई। संगठनों के अनुसार पदोन्नति सूची जारी होने के महीनों बाद काउंसलिंग के लिए अचानक TET से संबंधित जानकारी मांगी गई। शिक्षकों ने इसे पदोन्नति प्रक्रिया में विसंगति बताते हुए संबंधित आदेश में संशोधन की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान जिले की स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सत्र 2025-26 के पात्र शिक्षकों को अभी तक मुख्यमंत्री शिक्षक अलंकरण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। इसे जल्द प्रदान करने की मांग की गई। इसके साथ ही सत्र 2025-26 में संचालित बालवाड़ी केंद्रों का लंबित मानदेय तत्काल जारी करने की मांग भी रखी गई। शिक्षकों ने विभागीय सूचना व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। उनका कहना है कि कई बार महत्वपूर्ण विभागीय सूचनाएं समय पर शिक्षकों तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे निर्धारित समयसीमा में जानकारी जमा करने में परेशानी होती है। संयुक्त मोर्चा ने सूचना तंत्र को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की मांग की है। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षक संवर्ग आगे की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि शिक्षा सचिव नवा रायपुर और कलेक्टर बेमेतरा को भी भेजी गई है। प्रदर्शन में रविन्द्र राठौर, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत, मोहम्मद यासीर इरफान, देवेंद्र हरमुख, बसंत कौशिक, अश्वनी कुर्रे, सिराज बख्स, आदित्य गौरव, प्रेम नारायण शर्मा, अशोक कुमार धुर्वे, पोखण साहू, चंद्रशेखर पटेल, अजय यादव, गंगाधर दुबे, बाबूलाल गोयल, गेंदराम वर्मा, ओम नारायण साहू, राजा वर्मा, दीपक राजपूत, पूर्णेंद्र तिवारी, मनीष पाटील, सुनील साहू, सुकन्या राजपूत, सुनीता

हरियाली तीज मिलन समारोह का आयोजन

रायपुर। महिला राजपूत क्षत्रिय समाज, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर की महिलाओं ने मिलकर रायपुर में हर्षोल्लास के साथ हरियाली तीज मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम में सभी का तिलक एवं राम नाम के दुपट्टे से स्वागत किया गया। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के माध्यम से समाज की एकता, संस्कार एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने तथा युवा पीढ़ी को अपने हुनर को निखारने और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली का संदेश दिया गया।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में नजर आयेगे वॉर्नर, युवराज और विलियर्स सहित कई स्टार बल्लेबाज

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज एबी डी विलियर्स और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो सहित कई दिग्गज क्रिकेटर 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्लयूसीएल) के तीसरे सत्र में खेलते नजर आयेंगे। ऐसे में प्रशंसकों को एक बार फिर इन बल्लेबाजों का आक्रामक खेल देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग से कई पूर्व क्रिकेटरों को एक मंच मिलता है। इस बार बांग्लादेश के महमुदुल्लाह रियाद जैसे खिलाड़ी भी इस लीग में शामिल हो रहे हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का यह तीसरा सत्र है। वहीं लीग के पहले सत्र में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर खिताब जीता था। वहीं, दूसरे सत्र में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर ट्रॉफी जीती थी।

इस बार टूनार्मेंट में बांग्लादेश चैंपियंस को भी शामिल किया गया है, जिससे टूनार्मेंट में नई टीमों और खिलाड़ियों का प्रवेश होगा होगा और प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ने की उम्मीद है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की ओर से कहा गया है कि दो सफल सत्र के बाद, लीग का तीसरा सत्र अधिक रोमांचक रहने की उम्मीद है। ये सत्र प्रशंसकों को एक अभूतपूर्व अनुभव देने का वादा करता है, जहां क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर अपने पुराने और आकर्षक अंदाज में नजर आएंगे। लीग का लक्ष्य रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को एक मंच देना है, जिससे वे खेल के प्रति अपने जुनून को जीवित रख सकें और प्रशंसकों का मनोरंजन कर सकें। लीग के सीईओ हर्षित तोमर ने आगामी सीजन को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, सीजन 3 बहुत खास होने वाला है। इस सत्र का आयोजन इंग्लैंड से बाहर होगा। इस सत्र में क्रिकेट के सबसे बड़े नाम और ऐसे स्टार्स को लेकर आएंगे जिनके बारे में प्रशंसक सोच सकते हैं।

यशस्वी के बदले पंड्या को शामिल कर सकती है रॉयल्स

मुम्बई। बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आईपीएल के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स की जगह पर किसी और टीम से खेलते दिख सकते हैं। इसका कारण ये है कि रॉयल्स यशस्वी को आईपीएल 2027 से पहले रिलीज कर सकता है। ये भी अटकलें हैं कि वह मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को शामिल कर सकता है। ऐसे में यशस्वी मुम्बई के पास चले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसर राजस्थान प्रबंधन और यशस्वी के बीच मतभेद है। इसका सबसे बड़ा कारण रियान पराग को उनसे पहले कप्तानी सौंपना है। हालांकि, इस पूरे मामले पर रॉयल्स और यशस्वी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

गौरतलब है कि आईपीएल 2026 में यशस्वी ने 16 मैचों में 427 रन बनाए थे, जिसमें उनका औसत 30.50 और स्ट्राइक रेट 152.50 रहा। इस सत्र में वे केवल तीन अर्धशतक ही लगा सके। दूसरी ओर उनके सलामी जोड़ीदार वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 237.30 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। जिससे यशस्वी के प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। का प्रदर्शन थोड़ा फीका पड़ गया।

वहीं रॉयल्स को इस समय एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है। पिछले साल भी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक बड़े ट्रेड में संजू सैमसन के बदले सैम करन और रवींद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि, सैम करन चोट के कारण उस सीजन का एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे। ऐसे में, हार्दिक पंड्या जैसा एक अनुभवी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर उनकी इस जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो सकता है।

पंड्या के ट्रेड को लेकर पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें भी हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर रही हैं।

मुंबई इंडियंस के लिए पंड्या की कप्तानी में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2020 में अपना आखिरी आईपीएल टाइटल जीतने के बाद से टीम फाइनल में नहीं पहुंची है। मुंबई ने आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक को गुजरात टाइटंस से ट्रेड के जरिए हासिल किया था।

रूट को कप्तान बनाया जाना सही: ब्रूक

लंदन। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अनुभवी बल्लेबाज जो रुट को कप्तान बनाये जाने को एक सही कदम बताया है। बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद रुट को कप्तानी दी गयी जबकि ब्रूक भी कप्तानी के दावेदार थे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और इस बदलाव के दौरान रूट को कप्तानी की जिम्मेदारी दिये जाने से टीम को लाभ होगा। इंग्लैंड टीम 19 अगस्त से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है, जिसमें रूट एक बार फिर कप्तानी की कमान संभालेंगे। ब्रूक जून में स्टोक्स के संन्यास के समय उप-कप्तान थे, उन्होंने रूट को फिर से कप्तान बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। ब्रूक ने कहा, रूट को कप्तान बनाने का फैसला एकदम सही है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि वह क्या कर सकते हैं। वह निश्चित रूप से इस काम को संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं। सीमित ओवरों की टीम के कप्तान ब्रूक ने टेस्ट डेब्यू करने के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दौरों पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां टेस्ट में उनका औसत क्रमशः 84.10 और 75.44 रहा पर अक्टूबर 2025 में एक नाइटक्लब में हुए झगड़े के बाद उनका करियर कठिन दौर में फंस गया। इस घटना पर ब्रूक ने कहा, यह एक कठिन दौर था, खासकर जब मैं घर पर था और मीडिया का सामना करने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगता है कि उस दौरान मैंने जो जज्बा दिखाया। मैदान पर जाकर अच्छा प्रदर्शन करना और सफेद गेंदब टीम की अच्छी तरह से कप्तानी करना। उस पर मुझे खुद गर्व है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इससे मुझे मदद मिली पर इसने मुझे एहसास कराया कि इंग्लैंड का कप्तान होना कितनी बड़ी बात है। यह सिर्फ मैदान पर लीडरशिप की बात नहीं है। अगर आप मैदान के बाहर भी जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कर सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।

बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर फेरान अब पीएसजी से खेलते दिखेंगे

मैड्रिड। विश्वप कप में स्पेन की टीम को जीत दिलाने वाले बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर फेरान टोरेस अब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से जुड़ सकते हैं। बार्सिलोना अपने फारवर्ड टोरेस को करीब 50 मिलियन यूरो में फ्रांसीसी क्लब को बेचने के लिए तैयार है। इस मामले में दोनों क्लबों के बीच बातचीत पूरी हो गयी और अब केवल जरूरी औपचारिकताएं ही बची हैं। बताया जा रहा है कि फेरान का पीएसजी के साथ पांच साल का करार है। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अभी मेडिकल जांच और कुछ कागजी कार्रवाई होनी बाकी है।

गौरतलब है कि टोरेस को जनवरी 2021 में मैनचेस्टर सिटी ने 55 मिलियन यूरो से अधिक की रकम लेकर बार्सिलोना को बेचा था। उसके बाद से ही वह स्पेनिश क्लब के साथ बने हुए हैं। हालांकि, क्लब में उनका सफर हमेशा एक प्रमुख शुरूआती खिलाड़ी के तौर पर नहीं रहा। हांसी फ्लिक के 2024 में टीम की जिम्मेदारी संभालने के बाद, टोरेस को मुख्य रूप से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के विकल्प के तौर पर सेंटर फारवर्ड की भूमिका में उपयोग किया गया। इसके बावजूद, उन्होंने सीमित अवसरों का पूरा लाभ उठाया भुनाया है और कई मुकाबलों में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरकर टीम के लिए निर्णायक साबित हुए। पिछले दो सत्रों में, उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 94 मैचों में 40 गोल किए हैं। उनकी गति, गेंद पर नियंत्रण और आक्रमण में कई स्थानों पर खेलने की क्षमता ने उन्हें बार्सिलोना के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी बनाए रखा।

टोरेस ने हाल ही में स्पेन की विश्व कप जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। पिछले महीने स्पेन और अर्जेंटीना के बीच हुए विश्व कप फाइनल में उन्होंने अतिरिक्त समय में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा था, जिससे स्पेन ने दूसरी बार विश्व कप खिताब जीता। राष्ट्रीय टीम के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाने के कुछ ही समय बाद उनका क्लब बदलना फुटबॉल जगत में खासा चर्चा का विषय बन गया है। टोरेस ने अपने फुटबॉल करियर की शुरूआत वालेंसिया की युवा व्यवस्था से की थी, जिसके बाद वह मैनचेस्टर सिटी और फिर बार्सिलोना का हिस्सा बने। अब पेरिस सेंट-जर्मेन में उनका जाना उनके करियर को एक नई महत्वपूर्ण दिशा दे सकता है।

बार्सिलोना के लिए यह फैसला आक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के क्लब से अलग होने के बाद टीम को आगे के मोर्चे पर नए विकल्पों की सख्त जरूरत है, और टोरेस के जाने से यह जरूरत और भी बढ़ जाएगी।

आईपीएल में खिलाड़ियों को ट्रेड किये जाने की रकम का खुलासा करें फ्रैंचाइजी : गावस्कर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि आईपीएल में ट्रेड के जरिये खिलाड़ियों के एक टीम से दूसरे में जाने की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिये।

गावस्कर के अनुसार ऐसा करने से अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजियों को भी यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि सभी टीमें लीग निर्धारित सैलरी कैप का सही ढंग से पालन कर रही हैं या नहीं।

गावस्कर ने कहा वर्तमान में, किसी खिलाड़ी के ट्रेड करार पर उसकी डील की रकम की जानकारी केवल दोनो ही फ्रेंचाइजियों, खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को ही रहती है। अन्य टीमों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसी कारण दूसरी टीमों को यह पता नहीं चलता कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने लिए तय सैलरी कैप का पालन किया है या नहीं। गावस्कर ने कहा कि ट्रेड डील केवल दो पार्टियों का मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी लीग पर पड़ता है। ऐसे में

विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग होने के कारण आईपीएल को अपनी कार्यप्रणाली में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता बनाए रखना चाहिये।

। पूर्व कप्तान का मानना है कि ट्रेड से जुड़ी हर जानकारी को सार्वजनिक करने से लीग की विश्वसनीयता बढ़ेगी और किसी भी तरह के सवाल या संदेह नहीं रहेंगे। उनका मानना है कि यदि सैलरी कैप का सही से पालन हो रहा है, तो इस जानकारी को छिपाने का कोई मतलब नहीं है।

गौरतलब है कि हाल के समय में आईपीएल ने कई बड़े खिलाड़ियों के ट्रेड्स देखे हैं, जो इस मामले की प्रासंगिकता को और बढ़ाते हैं। 2026 सीजन से पहले संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड हुआ था, जिसकी मौजूदा लीग फीस 18 करोड़ रुपए बताई गई। इसी तरह, 2026 सीजन समाप्त होने के बाद, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव जैसे प्रमुख खिलाड़ियों का भी ट्रेड हुआ। पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में लौटे और उनकी नई फीस 15 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, जबकि कुलदीप यादव दिल्ली से लखनऊ गए और उनकी फीस 13.50 करोड़ रुपए है। ये सभी ट्रेड्स बड़े नामों से जुड़े थे और इनकी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक होने पर लीग की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठते। इससे ये भी पक्का हो जाएगा कि लीग अपनी निर्धारित नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन कर रही है या नहीं। इससे सभी फ्रैंचाइजियों को समान अवसर मिलेंगी।

कारोबार

वैश्विक तनाव से घरेलू शेयर बाजार फिसला

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। सुबह शुरूआत में सेंसेक्स 260 अंक गिरकर 77,468.44 पर और निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ 24,234.75 पर कारोबार कर रहा था। शुरूआती कारोबार में निफ्टी50 में इंफोसिस सहित कई आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। सेक्टरों में आईटी और रियल्टी सबसे ज्यादा कमजोर रहे, जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने बाजार की गिरावट के बीच मजबूती दिखाई। बाजार के जानकारों के मुताबिक निफ्टी लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की धारणा पर लगातार दबाव डाल रही हैं। उन्होंने 24,150 को तत्काल सपोर्ट और 24,450-24,500 को अहम रेजिस्टेंस बताया। बाजार में सुधार कच्चे तेल की कीमतों में नरमी या भू-राजनीतिक तनाव कम होने पर निर्भर करेगा। वहीं सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 281 अंक और निफ्टी 78 अंक से अधिक टूटा। बढ़ती तेल कीमतों और बिकवाली के दबाव से निवेशकों के करीब 79,000 करोड़ रुपये डूब गए।

रुपया सात पैसे टूटकर 95.68 प्रति डॉलर पर

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार के कारोबारी दिन रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दशार्ता है। रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती एफसीएनआर (बी) विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा को अनुमान से पहले बंद किए जाने से भविष्य में डॉलर के प्रवाह को लेकर चिंता भी बढ़ी है।

टीवी रेटिंग्स ठप: विज्ञापन बाजार पर मंडराया संकट

विज्ञापन खर्च घटकर 2025 में 26,300 करोड़ रहने का अनुमान

नई दिल्ली। भारत के दूसरे सबसे बड़े टीवी बाजार में टेलीविजन दर्शकों की माप और रेटिंग का काम 1 जुलाई से पूरी तरह ठप पड़ा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को नई टेलीविजन रेटिंग नीति के तहत उसके पंजीकरण नवीनीकरण पर फैसला होने तक यह काम रोकने का निर्देश दिया है। इस अनिश्चितता ने विज्ञापन उद्योग में चिंता बढ़ा दी है, खासकर त्योहारी सीजन के मद्देनजर। एक महीने से अधिक समय से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीवी बाजार में टीवी रेटिंग का काम पूरी तरह ठप है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक नई टेलीविजन रेटिंग नीति के तहत बीएआरसी के पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता। मौजूदा समय में पारंपरिक टीवी पर विज्ञापन खर्च लगातार घट रहा है, जो 2023 में 31,200 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 26,300 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि, जुलाई में विज्ञापन खर्च पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं दिखा, क्योंकि अधिकांश सौदे पहले ही हो चुके थे। लेकिन अगस्त से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन में टीवी पर विज्ञापन खर्च सबसे अधिक होता है। यदि रेटिंग आंकड़ों का यह संकट जारी रहता है, तो कई विज्ञापनदाता टीवी पर अपने खर्चों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इस स्थिति का असर विभिन्न प्रसारण कंपनियों पर अलग-अलग पड़ेगा। जियोस्टार, जी या सोनी जैसे बड़े नेटवर्क शायद पुराने दर्शक आंकड़ों और उनकी बाजार हिस्सेदारी के आधार पर विज्ञापन प्राप्त कर लें, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं या छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करने वाले छोटे ब्रांडों और चैनलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नई टेलीविजन रेटिंग नीति का मूल उद्देश्य अच्छा है, जिसका लक्ष्य रेटिंग के क्षेत्र में दूसरी कंपनियों के लिए भी प्रवेश आसान करना है। इस नीति में कम से कम 80,000 मीटर लगाने की व्यवस्था की गई है, जो बार्क के मौजूदा 58,000 मीटर के मुकाबले काफी अधिक है। इन मीटरों की संख्या हर साल बढ़ाई जानी है और आखिरकार यह संख्या 1,20,000 तक पहुंचनी है।

जल्द पेश होगी मारुति बलेनो फेसलिफ्ट अपडेट मॉडल

मुंबई। करीब 4 साल बाद मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो फेसलिफ्ट अपडेट को 5 सितंबर को पेश करने की पुष्टि की है। मारुति ने हाल ही में ब्रेजा को भी अपडेट किया था। बलेनो फेसलिफ्ट के टेस्ट मॉडल कई बार देखे जा चुके हैं। पिछले स्पाई शॉट्स के आधार पर बलेनो फेसलिफ्ट में नया फ्रंट फेसिया मिल सकता है। इसमें अपडेटेड बंपर, नए डिजाइन वाले डीआरएल और नई ग्रिल लेआउट की उम्मीद है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। हालांकि, कार का ओवरऑल सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। रियर में नए बंपर डिजाइन जैसे मामूली बदलाव मिल सकते हैं। टेल लाइट्स में बदलाव की उम्मीद नहीं है। बलेनो फेसलिफ्ट में नया इंटीरियर थीम और अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन दिया जा सकता है। सेंटर कंसोल लेआउट को भी नए सिरे से डिजाइन किए जाने की उम्मीद है। 2022 में नई बलेनो लॉन्च हुई थी। उस समय इसमें हेड-अप डिस्प्ले, सेगमेंट में पहली 360 डिग्री कैमरा सुविधा और प्रीमियम केबिन जैसे फीचर्स दिए गए थे। समय बीतने के साथ 2026 में मौजूदा बलेनो में कुछ फीचर्स की कमी महसूस होती है। फेसलिफ्ट में सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और मौजूदा 9-इंच सेटअप से बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के कई फीचर्स भी बरकरार रह सकते हैं।

इनमें हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर अरकामिस साउंड सिस्टम, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और वॉशर के साथ रियर वाइपर भी मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए कार में फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़े जाने की उम्मीद है। मौजूदा सेफ्टी फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

सोना-चांदी धड़ाम! एक दिन में 3,500 रुपए तक टूटे दाम

सोना 1,55,070 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी का भाव 2,35,450 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार खुलते ही सोने के दाम 1,000 रुपये तक और चांदी 2,600 रुपये तक नीचे आ गई।

सुबह एक घंटे के भीतर दोनों कीमती धातुओं में करीब 3,500 रुपये तक की गिरावट देखी गई, जिसने सोमवार की पूरी बढ़त को खत्म कर दिया। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह बाजार खुलने के बाद 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 870 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी में 2,598 रुपये की कमी आई और यह 2,35,450 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही थी।

मामूली अंतर देखने को मिला

मंगलवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 15,589 रुपये प्रति ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 14,290 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,692 रुपये प्रति ग्राम पर बिका। चांदी का भाव 250 रुपये प्रति ग्राम और 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रहा। देश के अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला।

मध्यप्रदेश बना निवेशकों का सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशनः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने उद्योग निवेश संवर्धन की सेंट्रल बॉडी मीटिंग में किया मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च सेंट्रल बॉडी की बैठक में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' में कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की 'भव्या' योजना (भारत औद्योगिक विकास योजना) के माध्यम से उद्योग विकास के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश में पर्याप्त लैंडबैंक के साथ बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने 25 से अधिक नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से व्यापार एवं उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश के पहले ₹पीएम मित्र पार्क₹ का भूमिपूजन किया था, जिसका कार्य बड़ी तेजी से प्रगति की ओर है। केंद्रीय मंत्रीगण ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने देश-दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्यप्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।

जीआईएस-2025 में मिले लगभग 30 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रोजगारपरक उद्योगों से देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इसी से हर वर्ग के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में बीते वर्ष को ह्यरोजगार एवं उद्योग वर्षह्न के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के माध्यम से प्राप्त 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 30 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर चुके हैं, जो प्रदेश में बढ़ते निवेश और उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी।

क्या है भव्या योजना ?

उल्लेखनीय है कि देश में निवेश प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 33 हजार 660 करोड़ रुपए की 'भव्या' (भारत औद्योगिक विकास योजना) एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य देश भर में 6 वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक) में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करके घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

आतंकी नेटवर्क का सफाया, आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो-टॉलरेंस का प्रमाण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सफल ऑपरेशन इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंसी रखता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले हर तत्व के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने देशवासियों को दी जानकारी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'एक्स' पर देशवासियों को जानकारी दी कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार करके उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो-टॉलरेंस नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है।

गृह मंत्री श्री शाह ने बताया कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस गुट के पास से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया। जिसमें आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल थे। यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था।

मीजल्स एवं मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय दल ने की वृहद समीक्षा

20 अगस्त से चलाया जाएगा मीजल्स-रूबेला कैचअप अभियान

भोपाल। बालाघाट जिले के प्रभावित क्षेत्रों में मीजल्स एवं मलेरिया के प्रकरणों आयुक्त स्वास्थ्य श्री धनराजू एस की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय दल ने 13 से 15 अगस्त 2026 तक जिले का सघन भ्रमण कर जांच की।

32 हजार 400 संभावित रोगियों की जांच

1 जुलाई से 14 अगस्त 2026 के मध्य विभिन्न ग्रामों में कुल 32 हजार 400 संभावित बुखार के रोगियों की जांच की गई। प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण गतिविधियां प्रारंभ की गईं तथा जांच के दौरान पाए गए गंभीर रोगियों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। आईसीएमआर एवं अन्य संस्थानों द्वारा की गई जांच में प्रभावित क्षेत्र के बच्चों में मीजल्स रोग की पुष्टि हुई है। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों में मीजल्स संक्रमण पाया गया। एनआईवी पुणे द्वारा की गई जांच में चांदीपुरा वायरस, वेस्ट नाइल फीवर वायरस तथा जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस सहित विभिन्न वायरस की जांच नेगेटिव पाई गई। जांच एवं उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर बच्चों में हुई मृत्यु के प्रमुख कारणों में मलेरिया एवं मीजल्स संक्रमण पाया गया है।

राज्य स्तरीय दल ने प्रभावित ग्रामों का दौरा कर स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया और मृत्यु के प्रकरणों के कारणों की विस्तृत समीक्षा की। प्रभावित क्षेत्रों में रोग नियंत्रण, जांच, उपचार, सर्वेलेंस एवं टीकाकरण की गतिविधियों को तेज करते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की विशेष निगरानी तथा प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।

दल में उपसंचालक आई.डी.एस.पी. डॉ. आश्विन भागवत, उपसंचालक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी व्ही.बी.डी.सी.पी. डॉ. हिमांशु जायसवार, उपसंचालक असंचारी रोग नियंत्रण डॉ. आशीष सक्सेना, और डॉ. सौरभ पुरोहित, उपसंचालक टीकाकरण शामिल रहे।

मास कैंप आयोजित कर जांच और वैक्टर नियंत्रण की कार्यवाही

राज्य स्तरीय दल द्वारा 14 अगस्त को प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखण्ड जिले का सर्वाधिक एन्डेमिक ब्लॉक है। पूर्व वर्षों के ट्रेंड के अनुसार जिले में जुलाई माह की शुरूआत से ही मलेरिया एवं बुखार के प्रकरणों में वृद्धि देखी जाती है। 17 जुलाई 2026 से बिरसा विकासखण्ड के तीन ग्राम बोंदारी, कोरका एवं कुंडेकासा में बुखार के रोगियों की संख्या में वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई थी। ये सभी प्रभावित ग्राम सोनगुड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत संचालित 05 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में आते हैं। इसकी सूचना जिले को प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर पर मास कैंप आयोजित कर जांच तथा वैक्टर नियंत्रण की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

20 अगस्त से मीजल्स-रूबेला कैचअप अभियान

स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य स्तरीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रभावित क्षेत्र में 20 अगस्त से मीजल्स-रूबेला अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 09 माह से 10 वर्ष तक के सभी बच्चों को मीजल्स-रूबेला वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। अभियान की शुरूआत सर्वाधिक प्रभावित एवं उच्च प्राथमिकता वाले विकासखण्डों से की जाएगी। बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा विकासखण्ड में 20 से 25 अगस्त 2026 तक एमआर कैचअप राउंड संचालित किया जाएगा। सोनगुड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी बच्चों का पुनः परीक्षण कराया जाएगा तथा अतिकुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। विकासखण्ड में निर्धारित मात्रा में टेक होम राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सभी आंगनवाड़ियों में नियमित रूप से गर्म एवं पका हुआ पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एमएसएमई विभाग में पद संरचना पुनर्गठन एवं भर्ती नियमों में संशोधन के लिए समिति गठित

भोपाल। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, स्वरोजगार सृजन, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं के विस्तार को देखते हुए विभाग की पद संरचना और भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विगत वर्षों में उद्योग संचालनालय सहित जोनल तथा जिला स्तरीय कार्यालयों के दायित्वों और कार्यक्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध मानव संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग और कार्यभार के अनुरूप पदों के पुनर्नियोजन के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

कृषक कल्याण वर्ष 2026 की मूल भावना के अनुरूप किसानों को मिल रही निर्बाध बिजली

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष 2026 की मूल भावना के अनुरूप मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसानों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है।

ग्रामीण परिवारों एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए अभिनव योजना के अंतर्गत मात्र 5 रुपए में स्थायी घरेलू एवं कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 2.21 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें 1.18 लाख कृषि एवं 1.02 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीपीएल श्रेणी के 10,327 उपभोक्ताओं को भी मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिये गए हैं।

पाँच रुपए में 2.21 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिले बिजली कनेक्शन

कंपनी द्वारा किसानों को सुगम एवं विश्वसनीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.48 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया है। योजना के माध्यम से किसानों के कृषि पंपों के लिए अधिक विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कृषि क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं उपभोक्ता सुविधाओं के विस्तार का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाकर उनकी सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा ग्रामीण परिवारों को सरल एवं सुगम विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

एम.पी. ट्रांसको शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन को मिली राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में प्रथम

भोपाल। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिले ने देश के सौ चयनित जिलों में जुलाई माह में प्रथम रैंक प्राप्त की है। यह उपलब्धि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वय से प्राप्त हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई और कृषि अधोसंरचनाओं को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। डिंडौरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो-कुटकी की खेती की जा रही है, जिससे 52 हजार 282 कृषक परिवार तथा 14 कृषक उत्पादक संगठन सीधे जुड़े हैं। जिले के पारंपरिक कोदो-कुटकी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हजार 36 किसानों से 3 हजार क्विंटल कोदो-कुटकी की उपार्जन एवं खरीदी पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान वर्ष में 10 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार के लिए जिले में 33 जैव संसाधन केंद्रों का निर्माण किया गया है।

किसानों की मेहनत का सम्मान बनाये रखने ढ़ाल है कवच योजना

4 अगस्त को मिली कवच योजना को मंजूरी

भोपाल। अन्नदाता किसान हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेत से बाजार तक कृषि मूल्य संवर्धन श्रृंखला को सुदृढ़ करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने, आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीक सहित प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन और संस्थागत वित्त की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर काम हो रहा है।

योजना को कब मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त 2026 को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहकारिता विभाग की ह्यकवच योजनाह्न को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनका सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है। कवच योजना से सहकारी समितियों से जुड़े ऐसे लगभग 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे, जिनके ऋण खातों में हुई गड़बड़ियों की जांच लंबित रहने के कारण वे शासकीय योजनाओं और नई ऋण सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी प्रक्रिया अथवा जांच के लंबित रहने का प्रतिकूल प्रभाव किसान की खेती और आजीविका पर अनिश्चितकाल तक न पड़े। इसी भावना के अनुरूप ह्यकवच योजनाह्न के जरिए प्रभावित किसानों को पुनः मुख्यधारा में लाकर उन्हें संस्थागत ऋण व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को नया ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये की सीमा तक विशेष निधि का निर्माण करेंगे। किसान हित में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

किसानों के हित में कवच योजना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। किसान की मेहनत का सम्मान हो, उनकी खेती-किसानी मजबूत हो और उसे आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी मिले, ह्यकवच योजनाह्न इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाला कदम है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित किसानों को राहत देने के साथ उन्हें फिर से सहकारी बैंकिंग प्रणाली एवं ऋण व्यवस्था की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष (2026) में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के उन हजारों किसानों के लिए नई उम्मीद की तरह है, जिनके लिए लंबित जांच के कारण नये ऋण प्राप्ति का रास्ता बाधित हो गया था। अब कवच योजना उनके लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने और संस्थागत वित्त व्यवस्था से फिर से जुड़ने का माध्यम भी बनेगी।

राज्य सरकार की किसान कल्याण नीति का मूल उद्देश्य किसान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उसकी मेहनत को सुरक्षित वित्तीय आधार उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि किसान को समय पर ऋण, कृषि आदान और उनके हित की सभी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि खेती-किसानी की गतिविधियां कतई बाधित न हों। यह योजना संस्थागत कृषि ऋण किसान की खेती के लिए महत्वपूर्ण आधार है। समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसान बीज, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई तथा अन्य आवश्यक कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। इससे किसानों को महंगे कर्ज पर निर्भरता से बचाने में भी मदद मिलती है। किसान कल्याण वर्ष-2026 में किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और उनके घरों में समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भिंड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और लोडिंग वाहन की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत

धान रोपाई का काम कर घर लौट रहे थे मजदूर, 22 घायल, 5 की हालत गंभीर

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे-719 पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास ट्रक और लोडिंग वाहन की जोरदार भिड़ंत में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और आसपास के गांवों के मजदूर ग्वालियर जिले के डबरा के पास चिनौर गांव में धान रोपाई का काम करने गए थे। काम पूरा करने के बाद सभी मजदूर लोडिंग वाहन से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे छीमका गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से लोडिंग वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोडिंग वाहन सड़क पर पलट गया और उसमें सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में लोडिंग वाहन अनियंत्रित हुआ और सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़का। दोनों वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर बेहद जोरदार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। हादसे की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला गया। डायल-108 की पांच एंबुलेंस और डायल-112 की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया।

गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। इनमें से तीन घायलों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के पीछे की वजह, दोनों वाहनों की रफ्तार और अन्य परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ले रही है

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार का विजन रखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं, उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी। मध्यप्रदेश द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा आधुनिक, विश्वस्तरीय और निवेश-तैयार औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।

बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सबार्नंद सोनोवाल तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी उपस्थित थे। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर अपने-अपने राज्यों का विजन रखा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को निरंतर गति दी जा रही है।

बैठक में मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास योजनाओं की प्रस्तुति से प्रदेश की निवेश क्षमता और औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया। भारत सरकार की इल्ळअश अ योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा फेज-क् राउंड-क में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत कुल 9,047.08 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल उद्धफ लागत 8,144.35 करोड़ रुपए है। इन औद्योगिक पार्कों को निवेश-तैयार और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से युक्त विकसित करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश में नए निवेश आकर्षित होने के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा।

मध्यप्रदेश द्वारा राउंड-कके अंतर्गत प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों को राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित रूप से वितरित किया गया है, ताकि औद्योगिक विकास के लाभ संपूर्ण राज्य में समान रूप से पहुंच सकें। प्रस्तावित 11 परियोजनाओं में अवंतिका इंडस्ट्रियल सेंटर (उज्जैन), भेंसोला (धार), पिपलरावांन-पालीकालन (देवास-शाजापुर), क्फरतलाम-पलसोड़ी, आष्टा इंडस्ट्रियल क्लस्टर (सीहोर), मसवासी ग्रांट (सागर), चैनपुरा (गुना), मोहना (ग्वालियर), धरमपुरा (जबलपुर), सिमरा (कटनी) और शिवसागर (रीवा) शामिल है। इन परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से अधिक है। भेंसोला औद्योगिक पार्क को टेक्सटाइल पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो धार स्थित भारत के सबसे बड़े ढट टक्ळफ्अ पार्क का विस्तार होगा तथा वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण वैल्यू चेन को समाहित करेगा। इसके अतिरिक्त, ये इंडस्ट्रियल पार्क फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, क्ळ एवं क्ळीर सहित विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करेंगे तथा इनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न करेंगे। प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मियों की सुविधा, सुरक्षा और कार्य के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत डे-केयर सेंटर, उउळश आधारित सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यक यूटिलिटीज, कैंटीन तथा अन्य सुविधाओं से युक्त हॉस्टल विकसित किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ उन्हें सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

औद्योगिक कॉरिडोर और नोड्स से निवेश को मिलेगी नई गति

प्रदेश में विकसित किए जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक नोड्स प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना को नई गति प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रही इन परियोजनाओं तथा राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियों का समन्वय प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विशेष संबोधन दिया। बैठक में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सबार्नंद सोनोवाल तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने भी संबोधित किया।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।